

अपने छोटे-छोटे कार्यों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है।

03 कांग्रेस ने तीनों सीट पर घोषित किए प्रत्याशी, मनोज तिवारी से टकराएंगे कन्हैया कुमार • 06 शिवराज सिंह चौहान का चुनाव लड़ रही हैं बहन-भाजियां • 08 भाजपा की सरकार ने दिया चम्बल परियोजना को मूर्त रूप : अग्रवाल

दिल्ली में चल रहे ड्राइविंग स्किल टेस्ट सेंटर क्या मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार है या नहीं ?

दिल्ली भारत देश की राजधानी में परिवहन विभाग द्वारा युवाओं से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो टेस्ट ऑटोमेटिक लिया जा रहा है क्या वह सीएमवीआर के अनुसार है या परिवहन विभाग के आला अधिकारी की इच्छानुसार, बड़ा सवाल ?



संजय बाटला
नई दिल्ली। आपकी जानकारी हेतु बता दें टोलवा द्वारा यह बात परिवहन विभाग के अधिकारियों से बैठकों में कई बार जाननी चाही पर कभी भी किसी के भी द्वारा इसका जवाब नहीं दिया गया। सड़कों पर अच्छी डेवलपमेंट स्किल रखने वाले ड्राइवर ही

वाहन चलाए यह सभी की इच्छा होगी पर अच्छी स्किल का अर्थ क्या है यह बड़ा सवाल है जिसको दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी भी बताना नहीं चाहते। किसी भी श्रेणी के वाहन के चलाने के लिए अलग अलग तकनीक की जरूरत होती है पर दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा चालित

ऑटोमेटिक टेस्ट सेंटर सिर्फ कांपैक्ट कार के अनुसार बनाए गए हैं ना की सिडान/एसयूवी कार के। इन ऑटोमेटिक टेस्ट सेंटर पर ऑटोमेटिक गियर कार से टेस्ट देना और पास करना बहुत सरल है। आपको पता ही होगा कि हल्के मोटर वाहन श्रेणी में ऑटो तीन पहिया, कार के साथ मिनी बस तक

आती है अब आप समझ ही सकते हैं की किस प्रकार दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी ने अपना इच्छा को दिल्ली के सभी युवाओं पर लागू कर दिया। अगर आप इन ऑटोमेटिक स्किल टेस्ट पर ऑटो तीन पहिया या ऑटोमेटिक गियर वाली कार से टेस्ट देंगे तो आप 99% फेल नहीं हो।

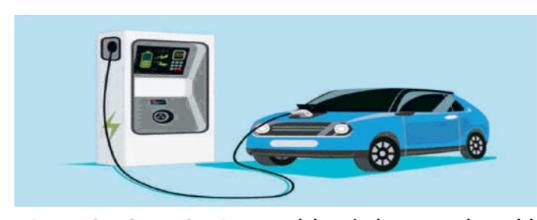
जनता से एक सवाल, प्रदूषण मुक्त वातावरण के प्रति

आप की नजर में टूटी सड़को, गंदी सड़को, सड़कों पर अनाधिकृत कब्जों, सड़कों पर खड़े रेहड़ी पटरी खोमचो, जाम लगाते और गलत ढंग से खड़े वाहनों, अनाधिकृत तरीके से सवारी सेवा में कार्यरत वाहनों के लिए कौन कौन है जिम्मेदार ? अपने विचार व्यक्त करें जिससे दुर्घटना और जाम मुक्त सड़कों के साथ प्रयावरित वातावरण में हम सब रह सके।

क्या भारत के लोग इलेक्ट्रिक वाहनों पर भरोसा कर पेट्रोल डीजल वाहनों की जगह प्रयोग कर सकते हैं ?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत में वित्त वर्ष 2023-24 से इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में काफी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तेजी से बढ़ाव हो चुका है। ऐसे में लोग विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड व्हीकल की ओर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि, ईवी की डिमांड भारत में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकी अधिक कीमतों के चलते अभी भी श्रेणी के वाहन के चलाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लोग कैसे अपनाएंगे और देश में इसका क्या भविष्य है ? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहनो के बिक्री का बाजार है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनो के रूप में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देश में इस समय परिवहन क्रांति का दौर है, जो इलेक्ट्रिक वाहन लाने में पूरी तरह से सक्षम है। भारत देश में इलेक्ट्रिक वाहनो का



परिवहन क्षेत्र में स्थायी परिवहन भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मजबूत राजनीतिक और सार्वजनिक इच्छाशक्ति की जरूरत है जो पर्यावरण और आर्थिक रूप से टिकाऊ हो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने और कार्बन के बढ़ते उत्सर्जनों को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनो को बढ़ावा दिया जा सकता है। परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनो के प्रयोग को बढ़ावा देकर एक आशाजनक भविष्य देने की कोशिश की जा सकती है। भारत उन गिने चुने देशों

में से एक है, जो प्रदूषण रहित देश बनाने के अभियान में इलेक्ट्रिक वाहनो को सपोर्ट कर रहा है। देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से वह एक बेहतर विकल्प की तलाश कर रहे हैं। भारतीय कस्टमर अब स्थाई उपाय के रूप में ईवी वाहनो पर भरोसा करने लगे हैं। भारत में ईवी की बढ़ती बिक्री इस बात का प्रमाण है। भारत सरकार भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ईवी पहुंचाने की पहल कर रही है। निकट भविष्य में हम हरे-भरे और प्रदूषण रहित समाज की कल्पना कर सकते हैं।

गैराज में खड़े वाहनो का कटाई चालान कोन जिम्मेदार

मुम्बई: आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बस मुम्बई में गैराज में खड़ी थी और पटना में और खरीद का चालान कट गया। मालिक का माथा तब ठनका का जब मोबाइल पर नुर्मा के ई-चालान आ गया। विभाग की लाल फीतावासी ऐसी कि पीछे बस और दोड़ कर गुजर लगाते रह गए लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अंततः 30,000 का नुर्मा भरने के बाद शांति मिली। जानकारी के मुताबिक लोकल लोकेशन टैगिंग डिवाइस, वीडियो की गलत रिपोर्टिंग के कारण ऐसी परेशानी आ रही है। बस मालिकों के पास अब के बिछारीत परमिट रुट से बाहर जाने या अन्य गड़बड़ियों को लेकर नुर्मा के गलत चालान आ रहे हैं। एक मामला मुम्बई में है जिसमें बस मालिक शिव कुमार चौधरी ने बताया है कि उनकी गाड़ी मुम्बई में गैरेज से लिए एक गैराज में खड़ी थी और पटना में रुट और टैगिंग का मामला बता कर दो गड़बड़ों पर नुर्मा के मासेज आ गया। माफ़ी के लिए कार्यालय के दोर लगाते रह गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बस मालिकों के लिए यह परेशानी का सबब बन गया है। परेशान बस मालिक ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से लेकर डीटीओ ऑफिस तक नुर्मा माफ़ी के लिए काफी भाग दोड़ लगाई। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने 30,000 जमा कर दिया उसके बाद मुक्ति मिली। उनके दो बसों पर नुर्मा लगाया गया था। बस मालिक शिव कुमार चौधरी ने बताया कि उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को गैरेज की रसीद भी दी। बताया कि उनकी गाड़ी उस तारीख को गैरेज में थी। लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई दो बसों पर 10,000 और 20,000 का नुर्मा जमा कराया गया। इस मामले में जिला परिवहन पदाधिकारी शशील कुमार ने बताया कि गाड़ी मालिक ने गाड़ी के गैराज में खड़ी होने का जो बिल दिया है उसे साबित नहीं होता है कि उसे दिन बस गैराज में खड़ी थी या परिवहन में थी। इसलिए नुर्मा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि गाड़ी मालिक के अश्वेतु पर दिमाग दिवार कर रहा है।

फेंक ई-चालान, कैसे करें असली-नकली में अंतर

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। हम जब भी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलते हैं, तो हमें सड़क एवं यातायात नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो आपकी गाड़ी का चालान कर दे। यही नहीं, अब तो रेंड लाइट या सड़क किनारे अन्य जगहों पर कैमरे भी लगे होते हैं, जो आपकी गाड़ी का चालान करते हैं। इसका मैसेज गाड़ी मालिक के मोबाइल पर जाता है, जिसे उसे भरना होता है। पर क्या आप जानते हैं कि आजकल फर्जी चालान के नाम पर भी काफी ठगी हो रही है। आप ऐसी गलती न करें, इसके लिए आपको कुछ बातों को जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं ये क्या हैं ?
क्या है फेंक ई-चालान ?
दरअसल, फेंक ई-चालान में वाहन मालिकों को फर्जी ई-चालान के मैसेज भेजे जाते हैं। इसमें उन्हें जानकारी दी जाती है कि उन्होंने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और उन्हें दिए हुए लिंक पर जुर्माना भरना है। वही, जैसे ही आप इस दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपको कोई एप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है या फिर किसी फेंक वेबसाइट पर आपको ले



जाया जाता है। इसके तुरंत बाद आपको जानकारी हैक करके आपको चपत लगा दी जाती है।
कैसे बचा जा सकता है ?
अगर आपके पास कोई चालान कटने का मैसेज आता है, तो सबसे पहले ये चेक करें कि ये मैसेज किसी पर्सनल नंबर से आया है या किसी और नंबर से कभी भी

मैसेज आते ही तुरंत रिप्लाय न करें और न ही दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। जब भी चालान का कोई मैसेज प्राप्त होता है, तो आप ई-चालान की आधिकारिक वेबसाइट <https://echallan.parivahan.gov.in/index/accuse-d-challan> पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि आया हुआ मैसेज असली है या नहीं।

बस हादसे पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला!

परिवहन विशेष न्यूज

महेंद्रगढ़। हरियाणा के महेंद्रगढ़ कनीना बस हादसे को देखते हुए अब चरखी दादरी प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है उन्होंने भी अपने जिले में एक टीम को गठित कर जिले के निजी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में चल रही प्राइवेट बसों को अच्छी तरह से चेक करने के आदेश दिए हैं और कड़ी कार्यवाही करने को लेकर बात कह दी है। स्कूल संचालकों को चेतावनी देते हुए बताया है कि अगर किसी स्कूल में किसी भी प्रकार की सुविधा या फिर बस सुविधा को लेकर किसी भी तरह की बच्चों को परेशानी हुई तो स्कूल के ऊपर एफआईआर दर्ज कर स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। महेंद्रगढ़ बस हादसे के बाद चरखी दादरी जिले के डीसी मनदीप कौर और एसपी पूजा वशिष्ठ ने संयुक्त रूप से प्राइवेट स्कूलों के अलावा निजी स्कूलों के बस ड्राइवर को चेतावनी



दी है। बसों को अच्छी तरह से चलने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। हम आपको बता दे की कनीना में प्राइवेट स्कूल बस हादसे में डीसी मनदीप कौर एवम् एसपी पूजा वशिष्ठ ने संयुक्त रूप से आरटीआई विभाग के कर्मचारियों के साथ निजी स्कूलों की बसों को अच्छी तरह से चेकिंग करने के आदेश दिए हैं और किसी भी बस के फिटनेस सर्टिफिकेट पूरी नहीं होने पर बस को जब्त करने और एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। बीते दिन दादरी जिले में निजी

स्कूलों की 12 बसों का चालान काट 200000 का भारी जुर्माना लगाया जा चुका है। डीसी मनदीप कौर और एसपी पूजा वशिष्ठ द्वारा प्रेस वार्तालाप में जानकारी देते हुए बताया कि जिला शिक्षा मौलिक अधिकारियों के नियम द्वारा हर निजी स्कूलों को पालन करना होगा अगर कोई स्कूल जिला शिक्षा मलिक अधिकारों का पालन नहीं करता है तो उनको बड़ी परेशानी होगी और भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर स्कूलों की बसों में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था पाई गई तो बसों को बंद कर दिया जाएगा। स्कूल बस के कागजात पूरे नहीं होने पर बस को बंद कर स्कूल के ऊपर भारी जुर्माना और एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी।

“सड़क सुरक्षा की पाठशाला, रिदमशाला की एक अनोखी पहल” : यातायात अराजकता का एक सामंजस्यपूर्ण समाधान

डॉ अंकुर शरण

नई दिल्ली। हॉर्न बजाने और अराजक यातायात के शोर में, सड़कों पर जीवन अक्सर तनाव और हादसा की सिम्फनी जैसा महसूस होता है। हालांकि, इस अराजकता के बीच, सड़क सुरक्षा के प्रति हमारे दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण पहल उभर रही है।

रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन और परिवहन विशेष के नेतृत्व में काम कर रहे सड़क सुरक्षा दस्ते के युवा स्वयंसेवकों ने सड़क सुरक्षा जागरूकता में एक मेगा ड्राइव चलाने के लिए हाथ मिलाया है। लेकिन यह सिर्फ एक और जागरूकता अभियान नहीं है; यह एक लयबद्ध क्रांति है जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण को बदलना है। लय-आधारित शिक्षा में अग्रणी संगठन, रिदमशाला के साथ साझेदारी करते हुए, इस पहल का उद्देश्य स्कूल और संस्थागत स्तर पर एक ड्रमिंग समुदाय बनाने पर एक परियोजना का संचालन करना है। यह विचार सरल लेकिन गहरा है: सड़क उपयोगकर्ताओं, विशेषकर युवाओं के बीच अनुशासन, समन्वय और जागरूकता की भावना पैदा करने के लिए लय और संगीत की शक्ति का उपयोग करना। सड़क सुरक्षा शिक्षा में ड्रम बजाने



को शामिल करके, यह पहल छात्रों को गतिशील और इंटरैक्टिव तरीके से संलग्न करने का प्रयास करती है। लय और लय के माध्यम से, प्रतिभागी न केवल यातायात नियमों का पालन करने का महत्व सीखते हैं, बल्कि टीम वर्क, फोकस और जिम्मेदारी का मूल्य भी सीखते हैं। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां सड़कें हॉर्न बजाने के बजाय ड्रमों की लयबद्ध ध्वनियों से भर जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक ड्रम सतर्क और सावधान रहने की याद दिलाता है। यह नवोन्मेषी दृष्टिकोण न केवल ध्यान, आकर्षित करता है, बल्कि सड़क सुरक्षा सिद्धांतों को अवचेतन में गहराई से समाहित भी करता है।

इसके अलावा, स्कूलों और संस्थानों के भीतर #Rhythm समुदाय को बढ़ावा देकर, इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की संस्कृति बनाना है। छात्र परिवर्तन के दूत बनते हैं, न केवल अपने साथियों के बीच बल्कि अपने परिवारों और समुदायों के बीच भी जागरूकता फैलाते हैं। रिदमशाला के साथ सड़क सुरक्षा जागरूकता में मेगा ड्राइव सड़क सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के हमारे तरीके में सावधान रहने की याद दिलाता है। यह सक्रिय जुड़ाव, रचनात्मकता और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देता है, यह पहचानते हुए कि स्थायी परिवर्तन के लिए

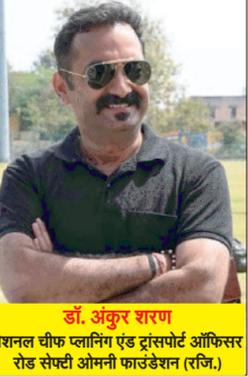
बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे बदलाव की आवाज सड़कों पर गूंजी है, आइए हम सफलता पूर्व अंजाम दिया है। सबसे अधिक प्रशंसा राहगीरों में की गई, जब एक लय में समाज हो या ताल - सब अच्छा लगता है और दिल को सुकून भी देता है।

राष्ट्र के युवाओं के नाम सड़क सुरक्षा, दुर्घटना और जाम मुक्त सड़कों के लिए सहयोग के लिए अपील लेख

हमारे राष्ट्र के प्रिय युवाओं,

आपकी ऊर्जा और तालमेल भारत को महानता और विश्व गुरु के रूप में उचित स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण है। हालांकि, जैसा कि हम प्रगति और सफलता के लिए प्रयास करते हैं, हमें सड़क सुरक्षा के महत्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, एक ऐसा मुद्दा जो हम सभी को प्रभावित करता है। हमारी चर्चाओं और अभियानों में, हमने कुछ सुनकर नियम देखे हैं जो रोड रेज से बचने और सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। ये नियम केवल दिशानिर्देश नहीं हैं बल्कि सिद्धांत हैं जो जीवन बचा सकते हैं और हमारे समाज को भलाई को बनाए रख सकते हैं।

शांत रहें: सड़क पर भावनाएं तेज हो सकती हैं, लेकिन दिमाग शांत रखना जरूरी है। शांत रहकर, हम स्थितियों को बढ़ने से रोक सकते हैं और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
यातायात कानूनों का पालन करें: यातायात कानून एक कारण से मौजूद हैं - व्यवस्था बनाए रखने और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए। आइए गति सीमा का सम्मान करें, ठीक से सिग्नल दें और ट्रैफिक सिग्नलों और संकेतों का पालन करें।
धैर्य का अभ्यास करें: भीड़ या निराशा के क्षणों में, धैर्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अनावश्यक हॉर्न बजाने और अचानक पैतरेबाजी से बचें और याद रखें कि धैर्य ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है।



डॉ. अंकुर शरण
नेशनल चीफ प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर
रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.)
सुरक्षित दूरी बनाए रखें: सुरक्षित दूरी का मतलब निकट-चूक और दुखद दुर्घटना के बीच अंतर हो सकता है। टकराव से रोकने के लिए हमेशा आगे वाले वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
टर्न सिग्नल का उपयोग करें: सड़क पर संचार महत्वपूर्ण है। अपने इरादों को पहले से ही इंगित करने के लिए टर्न सिग्नल का उपयोग करें, जिससे अन्य ड्राइवर आपके कार्यों का अनुमान लगा सकें और तदनुसार प्रतिक्रिया कर सकें।
ध्यान भटकाने से बचें: ध्यान भटकाने से हमारा ध्यान सड़क से भटक सकता है और अनाधिकृत रूप से सड़क का सामना करना पड़े, तो शांत रहें, उकसाव पर ध्यान न दें और यदि आवश्यक हो तो सहायता लें।
इन सुनकर निश्चिंत हो जायें: हम न केवल अपनी सुरक्षा करते हैं बल्कि सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक सामंजस्यपूर्ण ड्राइविंग वातावरण में भी योगदान करते हैं। आइए इन सिद्धांतों को बनाए रखें और सड़क पर उदाहरण पेश करने का संकल्प लें, यह सुनिश्चित करें कि हर यात्रा सुरक्षित हो।

भेजना, फोन पर बात करना या गाड़ी चलाने समय खाना खाना।
रास्ते का अधिकार: सम्मान सुरक्षित ड्राइविंग की आधारशिला है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य ड्राइवरों, पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों का साथ दें और सड़क पर हमेशा विनम्र रहें।
सतर्क रहें: दुर्घटनाओं के खिलाफ जागरूकता ही हमारा सबसे अच्छा बचाव है। सतर्क रहें, संभावित खतरों की जांच करें और सभी के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अन्य ड्राइवरों की गतिविधियों का अनुमान लगाएं।
सहनशील बनें: हम सभी इंसान हैं, और हम सभी गलतियाँ करते हैं। दूसरों की गलतियों पर आक्रामक प्रतिक्रिया करने के बजाय, आइए सहिष्णुता और समझ को चुनें। थोड़ी सी सहानुभूति सड़क पर बहुत आगे तक जा सकती है।
टकराव से बचें: सड़क पर टकराव केवल तनाव बढ़ाता है और सभी को जोखिम में डालता है। यदि किसी अन्य ड्राइवर से आक्रामकता का सामना करना पड़े, तो शांत रहें, उकसाव पर ध्यान न दें और यदि आवश्यक हो तो सहायता लें।
इन सुनकर निश्चिंत हो जायें: हम न केवल अपनी सुरक्षा करते हैं बल्कि सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक सामंजस्यपूर्ण ड्राइविंग वातावरण में भी योगदान करते हैं। आइए इन सिद्धांतों को बनाए रखें और सड़क पर उदाहरण पेश करने का संकल्प लें, यह सुनिश्चित करें कि हर यात्रा सुरक्षित हो।

दिल्ली से कांग्रेस ने तीनों सीट पर घोषित किए प्रत्याशी, मनोज तिवारी से टकराएंगे कन्हैया कुमार

परिवहन विशेष न्यूज

कांग्रेस ने आज अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। इसमें कुल 10 सीटों पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों का नाम शामिल है। इसी लिस्ट में दिल्ली की तीन सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी हैं। बता दें दिल्ली में आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले आप ने अपने चार सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के लिए आज अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। इसमें कुल 10 सीटों पर खड़े होने वाले प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इसी लिस्ट में दिल्ली की तीनों सीट के प्रत्याशियों के नाम भी शामिल हैं। इसमें उत्तर-पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया है।

बता दें, दिल्ली में आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले आप अपने चार सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। वहीं बीजेपी ने भी अपने सभी सातों प्रत्याशियों के नाम



जारी कर दिए हैं। इस तरह यह साफ हो गया है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली सीट पर मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार होंगे।

कांग्रेस के उम्मीदवार

उत्तर-पूर्वी दिल्ली- कन्हैया कुमार
चांदनी चौक- जेपी अग्रवाल



उत्तर-पश्चिमी दिल्ली- उदित राज

आप के उम्मीदवार

नई दिल्ली- सोमनाथ भारती
पूर्वी दिल्ली- कुलदीप कुमार
पश्चिमी दिल्ली- महाबल मिश्रा
दक्षिणी दिल्ली- सहीराम पहलवान



बीजेपी के घोषित प्रत्याशी

नई दिल्ली- बांसुरी स्वराज
उत्तरी चौक- प्रवीण खंडेलवाल
उत्तर-पूर्वी दिल्ली- मनोज तिवारी
पश्चिमी दिल्ली- कमलजीत सहरावत
दक्षिणी दिल्ली- रामवीर सिंह बिष्टू

कन्हैया कुमार और उदित राज को प्रत्याशी बनाकर क्या दिल्ली कांग्रेस में सभी खुश?

दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के संग्राम में कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी तो घोषित कर दिए लेकिन खासी जद्दोजहद के बाद भी नामों पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज के नाम पर प्रदेश कांग्रेस का खासा विरोध था लेकिन पार्टी आलाकमान ने प्रदेश के विरोध को दरकिनार कर इन दोनों को टिकट दे दिया।

नई दिल्ली। दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के संग्राम में कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी तो घोषित कर दिए, लेकिन खासी जद्दोजहद के बाद भी नामों पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज के नाम पर प्रदेश कांग्रेस का खासा विरोध था, लेकिन पार्टी आलाकमान ने प्रदेश के विरोध को दरकिनार कर इन दोनों को टिकट दे दिया।

यही वजह है कि टिकटों की घोषणा के साथ ही दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेताओं का मुंह फूल गया है। खुलकर तो कोई नहीं बोल पा रहा, लेकिन जिस टोन में बोल रहे हैं उससे साफ है कि टिकट बंटवारे से संतुष्ट नहीं हैं।

कन्हैया कुमार का लगातार हो रहा था विरोध

प्रदेश कांग्रेस के स्तर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार का लगातार विरोध हो रहा था। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली या फिर पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को टिकट दिए जाने की मांग की जा रही थी। इसी तरह उत्तर पश्चिमी सीट से उदित राज की जगह भी पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान या फिर पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार को टिकट दिए जाने की सिफारिश स्वीकृति कमेटी ने की थी।

जेपी अग्रवाल पर सभी की सहमति
चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल की मांग चौतरफा थी, उनको टिकट दिए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि सिर्फ एक मात्र जेपी अग्रवाल का टिकट ही सही मायने में सही है, बाकी तो बस पार्टी का भगवान मालिक है।

प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसियों का कहना है कि दिल्ली में पार्टी वैसे ही हाशिए पर खड़ी है, ऐसे में स्वीकृति कमेटी की सिफारिश को दरकिनार

चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल की मांग चौतरफा थी, उनको टिकट दिए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि सिर्फ एक मात्र जेपी अग्रवाल का टिकट ही सही मायने में सही है, बाकी तो बस पार्टी का भगवान मालिक है। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसियों का कहना है कि दिल्ली में पार्टी वैसे ही हाशिए पर खड़ी है, ऐसे में स्वीकृति कमेटी की सिफारिश को दरकिनार किया जाना संगठन के हित में बिल्कुल नहीं है।

किया जाना संगठन के हित में बिल्कुल नहीं है।
बाहरी नेताओं को टिकट देने पर खासा गुस्सा

सूत्रों का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस लगातार इस बात की मांग उठा रहा था कि दोनों जगहों से स्थानीय नेता को टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनकी बातों को दरकिनार कर दिया। कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर खासा गुस्सा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता पहले ही बाहरी लोगों को चुनाव लड़ाने के पक्ष में नहीं थे और लगातार चेतावनी दे रहे थे कि उनको टिकट लगाने वाले भी पूरे नहीं मिलेंगे।

जेपी अग्रवाल के आने से चांदनी चौक में मुकाबला हुआ दिलचस्प

चांदनी चौक सीट पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जेपी अग्रवाल के उतरने से भाजपा के साथ मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अग्रवाल ने इसी सीट से तीन बार 1984, 1989 और 1996 में लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया है। वहीं व्यापारियों के गढ़ में भाजपा ने व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को उतारा है वहीं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जेपी अग्रवाल की व्यापारियों में गहरी पैठ है।

माना जा रहा है कि चांदनी चौक सीट पर जेपी अग्रवाल एकबार फिर बेहतर प्रदर्शन के साथ आने वाले चुनाव में चौका सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पुराने वोट बैंक के साथ आम आदमी का समर्थन भी भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदान के दिन मतदाताओं के लिए सवैतनिक अवकाश की घोषणा की गई

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पी कृष्णमूर्ति ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के आदेश के कार्यान्वयन की घोषणा की, जो आर पी अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देता है। लोकसभा के आम चुनाव के संबंध में मतदान का दिन- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 25 मई, 2024 को निर्धारित है। आदेश के अनुसार, सभी पात्र कर्मचारी, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता हैं, मतदान के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश के हकदार

हैं। इसके अलावा, यह बताया गया है कि दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी शहरों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाताओं को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा और इसी तरह, पड़ोसी शहरों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को उनकी मतदान तिथियों के अनुसार सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

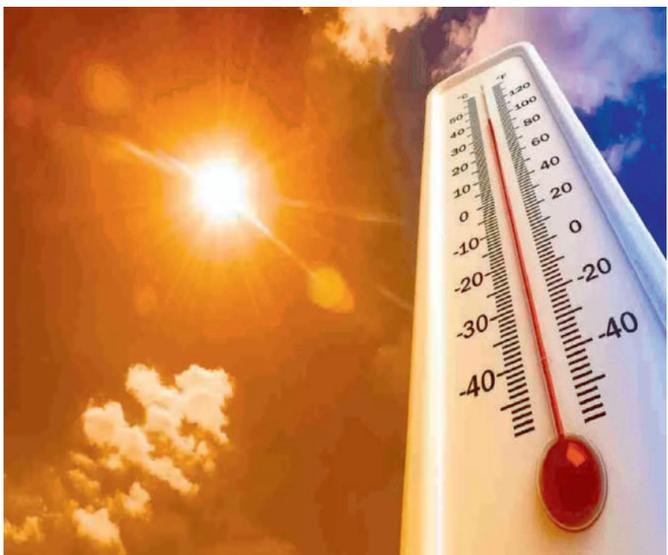
यह पहल मतदाता मतदान के महत्व और चुनावी प्रक्रिया को बढ़ावा देने में प्रत्येक नागरिक की मौलिक भूमिका को रेखांकित करती है। सवैतनिक अवकाश प्रदान करके, ईसीआई के मार्गदर्शन में दिल्ली के सीईओ का उद्देश्य दिल्ली के निवासियों के बीच निर्बाध भागीदारी को सुविधाजनक बनाना और मतदाता जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा, संबंधित सार्वजनिक, निजी या किसी अन्य प्रतिष्ठान के नियोक्ताओं से इस आदेश का अनुपालन करने



और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है कि उनके कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले। यह बताना है कि इस आदेश का अनुपालन न करने पर निर्दिष्ट प्रावधानों के

तहत जुर्माना के साथ-साथ सजा भी हो सकती है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के युवा मतदाताओं से इस अवसर का उपयोग करने और मतदान के दिन अपना वोट डालने की अपील की।

मार्च ने बढ़ते तापमान के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। मार्च ने बढ़ते तापमान के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यदि औद्योगिक काल से पहले की तुलना में देखें तो इस साल मार्च का औसत तापमान 1850 से 1900 के बीच मार्च में दर्ज किए गए औसत तापमान से 1.68 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। कॉर्पोरेट क्लाइमेट चेंज सर्विस (सी3एस) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान के यह आंकड़े इस बात को पुष्टा करते हैं कि पृथ्वी बड़ी तेजी से गर्म हो रही है और इसके प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। मार्च के दौरान वैश्विक स्तर पर सतह के पास हवा का औसत तापमान 14.14 डिग्री सेल्सियस (डिसे.) रिकॉर्ड किया गया। यह 1991 से 2020 के दौरान मार्च में दर्ज औसत तापमान से 0.73 अधिक है।

0.10 डिग्री सेल्सियस आठ साल में बढ़ा तापमान

इससे पहले सबसे गर्म मार्च वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था। 2016 की तुलना में 2024 में मार्च का तापमान 0.10 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इससे पहले जनवरी और फरवरी 2024 ने भी बढ़ते तापमान का रिकॉर्ड बनाया था। जनवरी में तापमान सामान्य से 1.66 और फरवरी 2024 में भी तापमान 20वीं सदी में फरवरी के औसत तापमान से 1.4 डिसे. ज्यादा था।

बढ़ते तापमान के कारण गहराते जा रहे जलवायु संकट के प्रभाव

कॉर्पोरेट क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार

लगातार बढ़ते तापमान के कारण जलवायु संकट के प्रभाव गहराते जा रहे हैं। जून 2023 से यह लगातार 10वां महीना है जब बढ़ते तापमान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यदि पिछले 12 महीनों यानी अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के तापमान पर गौर करें तो वह 1991 से 2020 के वैश्विक औसत तापमान से 0.70 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है।

ग्रीन हाउस गैसों में तत्काल कटौती की बहुत जरूरत
कॉर्पोरेट क्लाइमेट चेंज सर्विस की उप निदेशक सामंथा बर्गस कहती हैं कि मार्च 2024, लगातार दसवां महीना है जब हवा और समुद्र का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यदि पिछले 12 महीनों में तापमान के औसत को देखें तो वो औद्योगिक काल से पहले की तुलना में 1.58 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऐसे में हमें बढ़ते तापमान को रोकने के लिए ग्रीनहाउस गैसों में तत्काल कटौती करने की जरूरत है।

आर्कटिक में जमा समुद्री बर्फ साल के सबसे निचले स्तर पर

सी3एस के अनुसार ध्रुवों पर जमा बर्फ भारी तापमान के कारण लगातार पिघल रही है। मार्च में आर्कटिक में जमा समुद्री बर्फ साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इसका मासिक औसत विस्तार 1.49 करोड़ वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया जो सामान्य से कम है। मार्च 2024 में दर्ज समुद्री बर्फ का विस्तार 1980 और 1990 के दशक से करीब 25 फीसदी कम है।

एससी एसटी ओबीसी एंड माइनोंरिटी एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। 13 अप्रैल को जीबी पंत अस्पताल के एससी एसटी ओबीसी एवम माइनोंरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यालय में भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की 134 वीं जयंती का सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया। समारोह का आयोजन अस्पताल प्रशासन एवं एससी एसटी ओबीसी एवम माइनोंरिटी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मिलकर किया गया। बाबा साहेब की जयंती समारोह पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण डॉ. अनिल अग्रवाल जी चिकित्सा निदेशक के कर कमलो द्वारा डॉ. संगीता भसीन चिकित्सा अधीक्षक एवं डॉ. धर्मेंद्र गुप्ता अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक



जी की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेहमानों जिनमें अलग-अलग कर्मचारी संगठनों से आए पदाधिकारी, अस्पताल प्रशासन पदाधिकारी एससी एसटी ओबीसी

एण्ड माइनोंरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक श्री भगवान सक्सेना एवं पूर्व पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का एससी एसटी एसोसिएशन के चेयरमैन

फिरोज खान, संरक्षक नरेश कुमार मारोटिया, प्रधान संदीप कुमार, महासचिव जितेंद्र कुमार सक्सेना, अतिरिक्त महासचिव विजेंद्र चंदेलिया द्वारा धन्यवाद एवं प्रशस्ति पत्र देकर धन्यवाद किया गया।

दिल्ली की स्थिति पर रखी जा रही पैनी नजर, एलजी और आप सरकार के बीच टूटा संपर्क; 25 दिनों से कोई संवाद नहीं

आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉडिंग मामले में ईडी ने गत 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। करीब 25 दिन हो गए तब से वह हिरासत/जेल में ही है। विडंबना यह कि इस दौरान तिहाड़ से ही सरकार चलाने का असफल प्रयास हो रहा है। जबकि जेल नियमावली इसकी इजाजत ही नहीं देती। इस वजह से राजकुमार आनंद का इस्तीफा अटक हुआ है।

नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद देश की राजधानी में राजनिवास और दिल्ली सरकार के बीच संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। करीब 25 दिन से दोनों के बीच कोई सीधा या औपचारिक संवाद नहीं हुआ है। राजनीतिक स्तर पर आरोप प्रत्यारोप भले जारी हों, लेकिन दिल्लीवासियों के हित में कोई समीक्षा बैठक तक नहीं हो पा रही है। एलजी वीके सक्सेना के स्तर पर इस सारी स्थिति पर सूक्ष्म निगाह रखी जा रही है और बीच-बीच में वस्तुस्थिति से केंद्र को भी अवगत कराया जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से इस संदर्भ में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई।

आनंद का इस्तीफा तक फाइल में बंद पड़ा

आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉडिंग मामले में ईडी ने गत 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। करीब 25 दिन हो गए, तब से वह हिरासत/जेल में ही है। विडंबना यह कि इस दौरान तिहाड़ से ही सरकार चलाने का असफल प्रयास हो रहा है। जबकि जेल नियमावली इसकी इजाजत ही नहीं देती। इसी का नतीजा है कि जेल से कोई लिखित आदेश-निर्देश जारी होना तो दूर की बात, छह दिन से निवर्तमान समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा तक फाइल में बंद पड़ा है।

आनंद तकनीकी रूप से अभी भी मंत्री बने हुए
नियमानुसार यह इस्तीफा सीएम ही स्वीकृत करके एलजी को भेजेंगे और फिर एलजी इसे राष्ट्रपति को भेजेंगे। लेकिन जेल में बंद सीएम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ही नहीं सकते। मतलब, कोई काम ना करने के बावजूद आनंद तकनीकी रूप से अभी भी मंत्री बने हैं, जबकि औपचारिक रूप से इस्तीफा स्वीकृत न होने के कारण किसी नए मंत्री की नियुक्ति दूर तक नजर नहीं आ रही।

मौजूदा हालातों में दिल्ली सरकार का कामकाज प्रभावित न हो, इसके निमित्त एलजी



ने दो बार विभिन्न मंत्रालयों की बैठक भी लेनी चाही, किंतु कोई मंत्री राजनिवास नहीं पहुंचा। ऐसे में एलजी के स्तर पर इस पर भी पूरी निगाह रखी जा रही है कि आप नेताओं द्वारा जनता को गुमराह नहीं किया जाए कि उन्हें मिल रही सुविधाएं बंद हो जाएंगी। राजनिवास ने दो बार यह स्पष्ट भी किया है कि मुख्यमंत्री के जेल जाने से जनता को मिल रही सुविधाओं का कोई संबंध नहीं है।

राष्ट्रपति शासन लगाने की आशंका सिरों से गलत

राजनिवास अधिकारियों के मुताबिक केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे या नहीं, किसी अन्य को सीएम बनाएं या नहीं, यह उनका निर्णय है। लेकिन दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की आशंका वाले आरोप सिरों से

गलत हैं। ऐसे दूर-दूर तक कोई योजना नहीं है। सीएम को खुद ही देखना है कि लगातार लंबित हो रही फाइलें कैसे निपटाई जाएंगी, आचार संहिता खत्म होने पर कैबिनेट की बैठक कैसे होगी, नए मंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होगी और राजनिवास से तालमेल कैसे बैठाना जाएगा।

सीएम का यथासंभव सहयोग किया जा रहा

राजनिवास अधिकारियों ने दावा किया कि भले ही आप नेता कुछ भी आरोप लगाते रहें, लेकिन सीएम को यथासंभव सहयोग किया जा रहा है। घर के खाने के अलावा उन्हें अखबार और टीवी की सुविधा भी दी गई है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हर समय एक मेडिकल अटेंडेंट भी वहां रहता है।

'हर कार्यकर्ता हमारे साथ, स्थानीय युवाओं को फैक्ट्री में दिलाएंगे रोजगार', बसपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी का दावा

परिवहन विशेष न्यूज

बसपा ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को गौतमबुद्ध नगर से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। वह कांग्रेस में लंबे समय तक रहे। उन्होंने राजीव संजय गांधी से लेकर एनडी तिवारी के साथ काम किया। राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत है। प्रतिदिन 10 से 20 गांव और सोसायटियों में अपने लिए वोट मांग रहे हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर संवाददाता अंकुर त्रिपाठी ने उनसे बात की।

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर लोकसभा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होने वाला है। जैसे-जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे ही उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने गृह जनपद की गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट पर सिक्कराबाद के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सोलंकी पर भरोसा जताया है।

मूलरूप से खुर्जा से आने वाले राजेंद्र सिंह सोलंकी कांग्रेस में लंबे समय तक रहे। उन्होंने राजीव, संजय गांधी से लेकर एनडी तिवारी के साथ काम किया। राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत है। प्रतिदिन 10 से 20 गांव और सोसायटियों में अपने लिए वोट मांग रहे हैं। चुनाव में जीत को लेकर उनकी व पार्टी की रणनीति एवं क्षेत्र के मुद्दों पर संवाददाता अंकुर त्रिपाठी ने उनसे बात की। प्रस्तुत हैं उसके प्रमुख अंश...

प्रश्न - लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में आप पहली बार मैदान में हैं। बसपा कार्यकर्ताओं से सम्बन्ध कैसे बन पा रहे हैं?

देखिए बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ सम्बन्ध बहुत अच्छा है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और बसपा के प्रति कार्यकर्ता समर्पित हैं। कार्यकर्ता ही मुझे चुनाव लड़वा रहे हैं। हर विधानसभा में पार्टी के सिपाहियों ने मोर्चा संभाल रखा है। मैं प्रतिदिन उनके साथ गांवों और सोसायटियों में बेहतर तालमेल के साथ वोट मांगते हैं।

प्रश्न - लोकसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं? आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं?

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के चार बार के कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ। बसपा की सरकार में सबसे अधिक विकास के कार्य गौतमबुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में हुए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा मल्टी स्पेशलिस्ट सरकारी अस्पताल, चार इंटर कालेज व गांवों में रोड आदि बनवाईं। जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला भी बसपा सुप्रीमों ने रखी थी। हर मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद में कार्य करता है, लेकिन बहन मायावती ने पूरे प्रदेश का विकास किया। हर क्षेत्र को उन्नति की राह दिखाई। इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। 120 से 25 हजार फैक्ट्रियों हमारे किसानों की जमीन बनीं हैं। वादा किया गया था कि यहां के 60 प्रतिशत युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि जनता हमें चुनती है तो सबसे पहले इस मुद्दे पर ही कार्य होगा। सोसायटियों में रहने वाले लोगों की रजिस्ट्री कराई जाएगी। मेट्रो का विस्तार कराया जाएगा। सभी जातियों के उत्थान के लिए कार्य किए जाएंगे। धर्म और जाति की

समाजवादी पार्टी के कप्तान ने तो चुनाव से पहले ही हार मान ली थी। वह उम्मीदवारों के चयन में ही फेल हो गए। पहले उन्होंने डा. महेंद्र नागर को टिकट दिया फिर उनका टिकट काट कर राहुल अवाना को दे दिया। कमी लगी तो डा. महेंद्र नागर को फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया। उन्होंने तो परिणाम आने से पहले ही हार स्वीकार कर ली। बसपा की टक्कर भाजपा से है। भाजपा को लंबे अंतर से हार का सामना करना पड़ेगा। सांसद ने 10 सालों में कोई बड़े कार्य नहीं किए। किसान से लेकर युवा उनसे परेशान हैं। जनता के मुद्दे पर कार्य नहीं हुए। 110 सालों में कार्य किए जो तो मोदी के नाम पर दिए नहीं



Exclusive Interview राजेंद्र सिंह सोलंकी

राजनीति नहीं बल्कि बसपा विकास की राजनीति पर जोर दे रही है।

प्रश्न - बसपा काफी लंबे समय से सत्ता से बाहर है। संगठन के लोग दूसरे दलों में शामिल हो गए। संगठन की कमजोरी को कैसे दूर करेंगे?

गौतमबुद्ध नगर लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के साथ है। वह खुद के साधन से मुझे चुनाव लड़वा रहे हैं। पार्टी के लिए घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। कोई भी बसपा का कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में नहीं है। वह पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और बसपा के साथ का कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।

प्रश्न - खुर्जा, सिक्कराबाद व जेवर में आप हर जगह वोट मांग रहे हैं, लेकिन नोएडा, दादरी में सक्रियता कम है। यहां के मतदाता को अपने पक्ष में करने के लिए क्या योजना बनाई है? सिक्कराबाद विधानसभा के लोगों ने देवा बर विश्वास जताया। उनके विश्वास पर खरा भी उतरा। खुर्जा जन्मस्थली है। यहां ही पढ़ाई लिखाई हुई। खुर्जा और बुलंदशहर में सब जानते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गौतमबुद्ध नगर की विधानसभा में कोई नहीं जानता।

बाहर से आने वाले सोसायटी के लोगों में भले ही चेहरे से नहीं जानते हो, लेकिन वैसे सब जानते हैं। लोकसभा की पांचों विधानसभा में जनता का प्यार मिल रहा है। काफी लंबे अंतर से चुनाव में जीते होगी। प्रचार के दौरान हर विधानसभा में जनता का सहयोग पार्टी को मिल रहा है। मतदाताओं के बीच पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं।

प्रश्न - आपकी जीत का आधार क्या होगा? किस उम्मीदवार को आप अपना प्रतिद्वंद्वी मान रहे हैं? समाजवादी पार्टी के कप्तान ने तो चुनाव से पहले ही हार मान ली थी। वह उम्मीदवारों के चयन में ही फेल हो गए। पहले उन्होंने डा. महेंद्र नागर को टिकट दिया फिर उनका टिकट काट कर राहुल अवाना को दे दिया। कमी लगी तो डा. महेंद्र नागर को फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया। उन्होंने तो परिणाम आने से पहले ही हार स्वीकार कर ली। बसपा की टक्कर भाजपा से है। भाजपा को लंबे अंतर से हार का सामना करना पड़ेगा। सांसद ने 10 सालों में कोई बड़े कार्य नहीं किए। किसान से लेकर युवा उनसे परेशान हैं। जनता के मुद्दे पर कार्य नहीं हुए। 110 सालों में कार्य किए जो तो मोदी के नाम पर दिए नहीं

केंद्रीय विद्यालय में RTE के तहत दाखिले का आखिरी मौका, यहां जानिए आवेदन का तरीका और नियम

परिवहन विशेष न्यूज

अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का सपना देखने वाले अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है। अभिभावक शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिले के लिए केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 22 अप्रैल को लॉटरी के माध्यम से छात्रों को सीट आवंटित की जाएगी। 25 प्रतिशत सीट पर एससी एसटी ईडब्ल्यूएसबीपीएल और नॉन क्रीमी ओबीसी वर्ग का चयन होगा।

प्रश्न नोएडा। केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का सपना देखने वाले अभिभावकों के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आवेदन करने का 15 अप्रैल को आखिरी मौका है। अभिभावक केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय की 25 प्रतिशत सीट पर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल और नॉन क्रीमी ओबीसी वर्ग के छात्रों को दाखिला मिलेगा। 22 अप्रैल को लॉटरी के माध्यम से छात्रों को सीट आवंटित होगी। जनपद में चार केंद्रीय विद्यालय में कक्षा एक में दो संकल्पन हैं। हर संकल्पन में कक्षा एक में 32 सीट हैं। 132 सीट में आठ सीट

आरटीई के तहत रिजर्व है। इस सत्र में केंद्रीय विद्यालय में सीट कम कर दी गई है। पहले एक संकल्पन में 40 सीट होती थीं। अब बाल वाटिका की शुरूआत हो गई है। बाल वाटिका में आफलाइन प्रवेश हो रहा है।

यह है नियम
कक्षा एक में आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन करते समय छात्र की आयु छह वर्ष से अधिक और आठ से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में रहने वालों को पांच किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र वाले छात्र आठ किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आरटीई के तहत प्री प्राइमरी और कक्षा एक में दाखिला होगा।

जनपद में इन जगह हैं केंद्रीय विद्यालय
जनपद में चार केंद्रीय विद्यालय स्थित हैं। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा, केंद्रीय विद्यालय पी तीन ग्रेटर नोएडा, केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी और केंद्रीय विद्यालय एसएसजी सी आइएसएफ सूरजपुर में आरटीई के तहत कक्षा एक में 64 सीट हैं।

आरटीई के तहत एक अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। 15 अप्रैल तक आवेदन भरने की आखिरी तिथि है। 22 अप्रैल को पहली लॉटरी निकाली जाएगी। **प्रियंका त्यागी, प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय**

सामाजिक-आर्थिक विकास का वाहक बन रहा है मध्यम वर्ग



मध्यम आय वर्ग में इजाफा होने का मतलब साफ-साफ यह हो जाता है कि देश की अर्थ व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसे यों समझा जा सकता है कि मध्यम आय वर्ग या दूसरे अर्थ में हम मध्यम वर्ग की बात करें तो जीवन जीने का कोई आनंद लेता है तो वह मध्यम वर्ग ही है।

माने या ना माने पर इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी देश के आर्थिक-सामाजिक विकास में मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका रही है। यह केवल हमारे देश के संदर्भ में ही नहीं अपितु समूचे विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा तो कारण यही सामने आएगा। सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के बदलाव में मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका रही है। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरह से श्रमिक वर्ग उभर कर आया तो औद्योगिक क्रांति का ही बाई प्रोडक्ट मध्यम वर्ग का उत्थान माना जा सकता है। आर्थिक विश्लेषकों की माने तो आर्थिक विकास का कोई ग्रोथ इंजन है तो वह मध्यम वर्ग है। ज्यादा दूर नहीं जाए और केवल वर्तमान दशक की शुरुआत बल्कि 2021 की ही बात करें तो देश में 30 फीसद परिवार मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में आ गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि 2031 तक यह आंकड़ा बढ़कर 46 फीसद को छू जाएगा। यानी की इस दशक में बचे साढ़े पांच साल में भी मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में तेजी से सुधार होगा।

2021 में जहां 9.1 करोड़ परिवार मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में थे वहीं 2031 तक यह संख्या बढ़कर 16.9 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। किसी भी देश और उसकी अर्थ व्यवस्था के लिए यह अपने आप में किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं आंकी जा सकती। विश्लेषकों के अनुसार 5 लाख से 38 लाख सालाना आय वाले परिवारों को मध्यम आय वर्ग श्रेणी में माना गया है। यह भी समझना होगा कि मध्यम वर्ग का विस्तार का सीधा सीधा अर्थ गरीबी रेखा से लोगों का बाहर आना और बाजार प्रतिविधियों में तेजी आने का कारण मध्यम वर्ग ही है। मांग और आपूर्ति को भी मध्यम वर्ग के संदर्भ में ही देखा और समझा जा सकता है।

मध्यम आय वर्ग में इजाफा होने का मतलब साफ-साफ यह हो जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसे यों समझा जा सकता है कि मध्यम आय वर्ग या दूसरे अर्थ में हम मध्यम वर्ग की बात करें तो जीवन जीने का कोई आनंद लेता है तो वह मध्यम

वर्ग ही है। मध्यम वर्ग के लोग जीवन को जीने में विश्वास रखते हैं भले ही उन्हें श्रद्धा कृत्वा धृत पीवैत की मानसिकता के अनुसार जीवन यापन करना पड़े। यही कारण है कि मध्यम वर्ग दिल खोलकर पैसा खर्च करता है। इसका एक कारण सामाजिक ताने बाने की भाषा में हम कहें तो यह कहा जा सकता है कि बहुत कुछ वह दिखावे के लिए करता है। जीवन यापन की दिखावे की इस प्रतियोगिता में वह वो सब कुछ पाना चाहता है जो उसके परिवार, पड़ोसी, मित्राण या आसपास के लोगों के पास है। इसमें रहन-सहन, खान-पान, पहनना-ओढ़ना, शिक्षा और इसी तरह की अन्य वस्तुओं/साधनों को प्राप्त करना मध्यम वर्ग का ध्येय रहता है और इसी कारण बाजार में नित नए उत्पादों की मांग बढ़ती रहती है तो देश के जीवन स्तर का पता चलता है।

दरअसल मध्यम वर्ग द्वाइटी कॉलर का प्रतिनिधित्व करता है। वह इस श्रेणी में आ सकता है कि प्रतिदिन वह अधिक से अधिक साधन जुटाए, भले ही उसके लिए उसे उधार का सहारा लेना पड़े। यहां यह भी समझ लेना जरूरी हो जाता है कि उच्च आय वर्ग की अपनी समझ व पहुंच होती है। पहली बात तो उच्च आय वर्ग की दायरे में कम लोग हैं। उनकी पसंद ना पसंद अलग होती है। उनके लिए जो उत्पाद बाजार में आएंगे वो अलग श्रेणी के होंगे। मध्यम वर्ग लगभग उसी दौड़ में दौड़ने का प्रयास करता है। उच्च वर्ग के पास लक्जियरियस चोपहिया वाहन है तो उसकी मांग पहले चरण में चोपहिया वाहन व उसके बाद ज्यों ज्यों वह थोड़ा आगे बढ़ना चाहेगा अपनी पहुंच के सुविधाजनक चोपहिया वाहन पाने की कोशिश में जुट जाएगा। इसी तरह से बाजार की मांग को मध्यम वर्ग ही बढ़ाता है। तस्वीर हमारे सामने हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं दो दशक ही हुए होंगे कि घरों में पंखों की जगह कुल्लों ने ली और कुल्लों में भी हैंसियत अनुसार ब्राण्डेड कंपनियां से लेकर लोकल कंपनियों के कुल्लों ने घरों में जगह बनाई। आज तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आ गया है जिस एयर कण्डिशनिंग के लिए केवल सोचा जा सकता था वह आज घर घर में पहुंच गया है। कम से कम एक एसी तो मध्यम वर्गीय परिवार में देखने को आसानी से मिल जाएगा। इसे यों समझा जा सकता है कि मध्यम वर्ग के विस्तार के अनुसार बाजार में मांग बढ़ी तो नित नई कंपनियां बाजार में आईं और इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़े। यह तो एक उदाहरण मात्र है।

क्या गाजियाबाद के 'भगवा' किले पर फहराएगा 'तिरंगा'?

कमलेश पांडे
गाजियाबाद लोकसभा सीट की मुख्य चुनावी लड़ाई एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग और इंडिया गठबंधन की कांग्रेस-सपा-आप प्रत्याशी डॉली शर्मा के बीच होगी। हालांकि दलित और क्षत्रिय वोटों के सहारे बसपा प्रत्याशी नंद किशोर पुंडीर इस लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने में सफल हो जाएंगे।

देश की राजधानी नई दिल्ली से सटी औद्योगिक नगरी गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है। आम चुनाव 2024 के तहत यह दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा, इसलिए पक्ष-विपक्ष के बीच राजनीतिक तपिश बढ़ती जा रही है। यहां की मुख्य चुनावी लड़ाई एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग और इंडिया गठबंधन की कांग्रेस-सपा-आप प्रत्याशी डॉली शर्मा के बीच होगी। हालांकि दलित और क्षत्रिय वोटों के सहारे बसपा प्रत्याशी नंद किशोर पुंडीर इस लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने में सफल हो जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

अब आइए बात करते हैं उन पहलुओं पर जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं:-

पहला फैक्टर है- शहरी बनाम ग्रामीण। आमनीर गाजियाबाद महानगर के शहरी इलाकों में जहां भाजपा की पैठ मजबूत है, वहीं ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस के पक्ष में है क्योंकि उसने दलित, पिछड़े व वर्तमान सपा कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। जबकि बसपा की पैठ शहरी/ग्रामीण दोनों इलाकों के जातिविशेष में है। बता दें कि गाजियाबाद की 70 प्रतिशत आबादी शहरों में और 30 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। इस मामले में कांग्रेस पर भाजपा भारी पड़ सकती है।

दूसरा फैक्टर है- जातीय समीकरण। जो किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में विरले ही जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक, कुल 29



लाख 38 हजार 845 मतदाताओं वाली इस सीट पर सर्वाधिक 18 प्रतिशत ब्राह्मण, 15 प्रतिशत मुस्लिम, 14 प्रतिशत ठाकुर, 12 प्रतिशत गुर्जर, 10 प्रतिशत वैश्य, 16 प्रतिशत वंचित और 15 प्रतिशत अन्य मतदाता हैं। चूंकि भाजपा ने वैश्य, कांग्रेस ने ब्राह्मण और बसपा ने क्षत्रिय प्रत्याशी उतारे हैं। ये तीनों जाति भाजपा की हार्ड कोर समर्थक मानी जाती हैं।

शायद इसलिए भी कांग्रेस और बसपा ने उसी में संघ लगाने की पहल की है। हालांकि, जातीय समीकरण भी अभी भाजपा और समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत है। वर्तमान सपा कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। जबकि बसपा की पैठ शहरी/ग्रामीण दोनों इलाकों के जातिविशेष में है। बता दें कि गाजियाबाद की 70 प्रतिशत आबादी शहरों में और 30 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। इस मामले में कांग्रेस पर भाजपा भारी पड़ सकती है।

दूसरा फैक्टर है- जातीय समीकरण। जो किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में विरले ही जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक, कुल 29



हिंदुत्व भारी पड़ चुका है। क्षत्र धर्मानिपेक्षता पर राष्ट्रवाद हावी होकर बोल रहा है। वहीं, जातिविशेष पर बसपा की पकड़ से भी इकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए मौजूदा चुनावी लड़ाई दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है।

तीसरा फैक्टर है- सांप्रदायिक गोलबंदी। यह बात साफ है कि भाजपा को हिंदुओं के वोट थोक भाव में मिलते हैं, जबकि अल्पसंख्यक समाज का वोट रणनीतिक रूप से थोड़ा-बहुत। वहीं, कांग्रेस व उसके समाजवादी समर्थकों को अल्पसंख्यक समाज का वोट थोक भाव में मिलता है, जबकि बहुसंख्यक हिंदुओं के वोट जातीय आधार पर रणनीतिक रूप से थोड़ा बहुत। आंकड़े गवाह हैं कि जहां भी सांप्रदायिक गोलबंदी होती है, वहां भाजपा को ज्यादा, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में यह स्थिति उलट जाती है।

चौथा फैक्टर है- सरकारी कामकाज और विभिन्न मुद्दे। इस चुनाव में भाजपा पाना अब भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि गरीबी हटाओ के नारे

अपने शहर विधायक होने और उत्तरप्रदेश में राज्यमंत्री के रूप में सेवा देने के बारे में भी बता रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय मुद्दों की भी बात कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा कोरोना काल में अतुल गर्ग के यूपी के स्वास्थ्य राज्यमंत्री रहते हुए एी उनके द्वारा बरती गई लापरवाही पर लगातार उन्हें घेर रही हैं।

इसके अलावा, भाजपा द्वारा केंद्रीय मंत्री जनरल वी के सिंह का टिकट काटने पर भी उसकी पृष्ठ निरंर बनी हुई है। जबकि मतदाताओं को आड़े हाथों ले रही है। यही नहीं, स्थानीय मुद्दों पर भी उन्हें लगातार घेर रहे हैं। उनका आरोप है कि विगत 15 सालों से भाजपा के सांसद हैं, लेकिन मलिन बस्तियों तक विकास की किरण नहीं पहुंची है। गांवों में भी विकास नदारत है। इसलिए उन्होंने दो टुक कहा है कि गाजियाबाद का चुनाव वो स्थानीय मुद्दों पर भी लड़ेंगे। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, स्वच्छता, सुरक्षा, मेट्रो पहुंच आदि को वह सबके अनुकूल करने का इरादा रखती हैं। महंगाई व बेरोजगारी दूर करने का जज्बा रखती हैं। यहां पर कांग्रेस का पलड़ा कैडिडेट के तैवर की वजह से भारी है और यही तैवर उनकी असली

सियासी पूंजी है।

पांचवां फैक्टर है- संगठन और उसके दायरे। इस मामले में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर आरएसएस का परोक्ष हाथ हमेशा से ही रहता आया है। कांग्रेस भी अपने सेवा दल के सहारे देश पर लंबे समय तक राज कर चुकी है, जो अब कमजोर हो चुकी है। वहीं, नई आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम स्वरूप समाज में ऐसी प्रतिक्रिया बढी कि सेवा भाव अब लगभग गायब होते जा रहा है और श्रम मूल्य सामाजिक जीवन में प्रभावशाली स्थान लेता जा रहा है।

वहीं, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी सपा और आप के कैडर तो हैं, लेकिन ये भाजपा की रणनीति का मुकाबला कितने कागार ढंग से कर पाते हैं, सबकुछ इस बात पर ही निर्भर करेगा। हालांकि पारस्परिक सम्बन्ध बिठाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहीं, बसपा के पास लगभग 20 प्रतिशत कैडर वोट है, जिसके सहारे भारतीय राजनीति में उसकी पृष्ठ निरंर बनी हुई है। जबकि मतदाताओं को आड़े हाथों ले रही है। यही नहीं, स्थानीय मुद्दों पर भी उन्हें लगातार घेर रहे हैं। उनका आरोप है कि विगत 15 सालों से भाजपा के सांसद हैं, लेकिन मलिन बस्तियों तक विकास की किरण नहीं पहुंची है। गांवों में भी विकास नदारत है। इसलिए उन्होंने दो टुक कहा है कि गाजियाबाद का चुनाव वो स्थानीय मुद्दों पर भी लड़ेंगे। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, स्वच्छता, सुरक्षा, मेट्रो पहुंच आदि को वह सबके अनुकूल करने का इरादा रखती हैं। महंगाई व बेरोजगारी दूर करने का जज्बा रखती हैं। यहां पर कांग्रेस का पलड़ा कैडिडेट के तैवर की वजह से भारी है और यही तैवर उनकी असली

गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 28,847 मतदाता 16 से 20 अप्रैल तक घर बैठे कर सकेंगे मतदान

गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इससे पहले 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाता 16 से 20 अप्रैल तक अपने-अपने घर से ही मतदान करेंगे। इस कड़ी में घर-घर जाकर मतदान कराने के लिए एक टीम में पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी माइक्रो आब्जर्वर के अलावा वीडियोग्राफर और दो पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे।

गाजियाबाद। लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन इससे पहले 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाता 16 से 20 अप्रैल तक अपने-अपने घर से

ही मतदान करेंगे। मतदाताओं को उनके दिए हुए पते से ही मतदान कराने के लिए टीम गठित की है, जो निर्धारित तिथि पर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक पोस्टल बैलेट से मतदान कराएंगी।

मतदान टीम के अलावा रिजर्व टीम का कियोगा गठन उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि घर-घर जाकर मतदान कराने के लिए एक टीम में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, माइक्रो आब्जर्वर के अलावा वीडियोग्राफर और दो पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे।

गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 12,622 और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता



वाले 15825 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि रूट चार्ट के हिसाब से स्वीकृति देने वाले पर चलने-फिरने में अक्षम बुजुर्ग और दिव्यांगों के घर मतदानकर्मा जाकर मतदान कराएंगे।

26 अप्रैल को ईवीएम से कर सकेंगे मतदान
16 अप्रैल को यदि चिह्नित किए गए बुजुर्ग या दिव्यांग मतदाता घर पर नहीं मिलते तो एक बार फिर से अगले दिन टीम घर जाकर पोस्टल बैलेट से मतदान कराएंगी। इसके बाद वह तय तिथि 26 अप्रैल को ईवीएम से मतदान स्थल पर पहुंचकर मतदान कर सकेंगे। इसके लिए राजनीतिक दलों से अपना-अपना एजेंट नामित करने के लिए कहा गया है। इसके लिए गोविंदपुरम मंडी परिसर में पोलिंग पार्टियों को मतदान कराने के लिए प्रपत्र एवं सामग्री का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि कलक्ट्रेट परिसर में रिटर्निंग अफसर कार्यालय पर डाक मतपत्र के माध्यम से 16 से 21 अप्रैल तक मतदान कराएंगे।

पिछले वित्त वर्ष में देश से घटा वाहनों का निर्यात, जानिए क्या रही वजह

दोपहिया वाहनों के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष में 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 3458416 इकाई रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष में इस खंड में निर्यात 3652122 इकाई था। इसी तरह वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात 16 प्रतिशत घटकर 65816 इकाई पर आ गया। 2022-23 में वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात 78645 इकाई रहा था। तिपहिया वाहनों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 18 प्रतिशत घटकर 299977 इकाई रह गया।

नई दिल्ली। देश से वाहनों का निर्यात बीते वित्त वर्ष 2023-24 में 5.5 प्रतिशत घट गया है। आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स के संगठन सोसायटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) का कहना है कि कई विदेशी बाजारों में मौद्रिक संकट की वजह से देश से वाहनों के निर्यात में गिरावट आई है। बीते वित्त वर्ष में कुल वाहन निर्यात 45,00,492 इकाई रहा, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में यह 47,61,299 इकाई था। पिछले वित्त वर्ष में यात्री वाहनों का निर्यात 1.4 प्रतिशत बढ़कर 6,72,105 इकाई हो गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 6,62,703 इकाई था।

क्या रही आटो कंपनियों की स्थिति
समीक्षाधीन अवधि में मारुति सुजुकी ने 2,80,712 वाहनों का निर्यात किया। इससे पिछले वित्त वर्ष में मारुति का निर्यात 2,55,439 इकाई रहा था। हुंडई मोटर इंडिया ने पिछले वित्त वर्ष में 1,63,155 इकाइयों का निर्यात किया। इससे पिछले वित्त वर्ष में इसने



1,53,019 वाहनों का निर्यात किया था। किआ मोटर्स ने वर्ष के दौरान 52,105 वाहनों का निर्यात किया। जबकि फाक्सवैगन इंडिया ने पिछले वित्त वर्ष में 44,180 इकाइयों का निर्यात किया। निसान मोटर इंडिया और होडा कार्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में क्रमशः 42,989 और 37,589 इकाइयों का निर्यात किया। **वित्त वर्ष में 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई** दोपहिया वाहनों के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष में

5.3 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 34,58,416 इकाई रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष में इस खंड में निर्यात 36,52,122 इकाई था। इसी तरह, वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात 16 प्रतिशत घटकर 65,816 इकाई पर आ गया। 2022-23 में वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात 78,645 इकाई रहा था। तिपहिया वाहनों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 18 प्रतिशत घटकर 2,99,977 इकाई रह गया, जबकि 2022-23 में यह 3,65,549

इकाई था। सियाम के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल ने कहा कि कुछ देश जहाँ हम वाणिज्यिक वाहन और दोपहिया निर्यात के मामले में बहुत मजबूत हैं, विदेशी विनिमय से संबंधित मुद्दों का सामना कर रहे हैं। इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में कुछ अच्छा सुधार देखने को मिला है। खासकर दोपहिया वाहनों के खंड में। हमें पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर स्थिति में सुधार होगा।

इस साल भारत में किआ ला सकती है तीन नई कार, ईवी भी होगी पेश, जानें डिटेल

साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Kia भारत में एमपीवी और एसयूवी सेगमेंट में अपने उत्तम पादों की बिक्री करती है। अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए कंपनी की ओर से भारतीय बाजार में इस साल तीन नई कारों (Upcoming Kia Cars) को लाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Kia की ओर से किस सेगमेंट में किस नई गाड़ी को पेश किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में काफी कम समय में अपनी अलग पहचान बनाने वाली साउथ कोरियाई कार निर्माता Kia की ओर से पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से इस साल तीन नए उत्पादों को पेश किया जा सकता है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि कंपनी की ओर से किस सेगमेंट (Upcoming Kia Cars) में किस कार को लाने की तैयारी की जा रही है।

Kia EV9
साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Kia की ओर से भारतीय बाजार में अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी EV9 को भी इस साल भारत में पेश कर सकती है। कंपनी की ओर से इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को जनवरी 2023 में ऑटो एक्सपो में भी शोकेस किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को सिंगल चार्ज में करीब 500 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसके साथ ही इसे तीन रो सीट्स के साथ लाया जा सकता है।

Kia Clavis SUV



रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही किआ की ओर से एक और नई एसयूवी क्लाविस (Kia Clavis) को भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी

इस साल के अखिर तक या फिर अगले साल की शुरुआत में ही नई एसयूवी को देश में पेश कर सकती है। हालांकि अभी कंपनी की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी

नहीं दी गई है। लेकिन इस सब फोर मीटर एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान कई बार साउथ कोरिया के साथ ही भारत में भी देखा जा चुका है।

Kia Carnival
किआ की ओर से कार्निवल (Kia Carnival) को भी जल्द ही भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस लजरी एमपीवी को भी कंपनी की ओर से इस साल के अखिर या अगले साल के शुरू में पेश किया जा सकता है। कार्निवल को नई जेनरेशन में कंपनी की ओर से कई बदलाव किए जाएंगे, जिसमें डिजाइन, फीचर्स और इंजन तक शामिल होंगे। फिलहाल इस एमपीवी को डीजल इंजन के साथ ऑफर किया जा सकता है। सात सीटों वाली इस गाड़ी के पुराने वर्जन को कंपनी ने पिछले साल बंद कर दिया था।

तीन सेगमेंट में चार बाइक लाने के लिए तैयार Royal Enfield, जानें कब तक होंगी पेश ...

देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता Royal Enfield अपने पोर्टफोलियो को लगातार अपडेट कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से जल्द ही चार नई बाइक स (upcoming Bikes) को भारतीय बाजार में लाने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से किस सेगमेंट में किस बाइक को किन खूबियों के साथ लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। बुलेट और हिमालयन जैसी दमदार बाइक्स के साथ अपनी अलग पहचान रखने वाली Royal Enfield की ओर से जल्द ही नई बाइक्स को लाने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से किन चार बाइक्स को किन सेगमेंट्स में लाने की तैयारी हो रही है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Royal Enfield Bobber 350
350 सीसी सेगमेंट में कंपनी की ओर से नई बाइक के तौर पर बाबर 350 को लाने की तैयारी हो रही है। इस बाइक को क्लासिक 350 से प्रेरित होकर बनाया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर लाँन्च करने से पहले कंपनी इसकी टेस्टिंग कर रही है। जिस दौरान इसे देखा भी जा चुका है।

क्लासिक 350 के मुकाबले इसमें हैंडलबार, राउंड हेडलैप, फ्यूल टैंक, सीट, फीचर्स में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें कंपनी की ओर से जे सीरीज का 349 सीसी ऑयल कूल्ड इंजन दिया जाएगा जिसके साथ पांच स्पीड गियरबॉक्स होगा। जानकारी के मुताबिक इसे अगस्त-सितंबर 2024 के करीब पेश किया जा सकता है।

Royal Enfield Hunter 450
रॉयल एनफील्ड की ओर से हंटर 450 को भी इस साल भारत में पेश करने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेकेड रोडस्टर के तौर पर ऑफर होने वाली इस बाइक को भी कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। हिमालयन 450 की चैसिस पर बनने वाली इस बाइक में 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दिया जाएगा।

Royal Enfield Classic 650
फिलहाल कंपनी की ओर से 650 सीसी सेगमेंट तक ही बाइक्स को ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में कंपनी Classic 650 को भी ला सकती है। कंपनी की Shotgun 650 की तरह ही इसमें 648 सीसी का पैरलल ट्विन इंजन दिया जाएगा जिसके साथ छह स्पीड गियरबॉक्स होगा। इसमें वायर स्पोक रिम और ट्विन एर्गॉस्ट को भी दिया जा सकता है।

125cc सेगमेंट में आती हैं ये चार दमदार बाइक्स, माइलेज में भी हैं बेहतरीन, जानें



भारतीय बाजार में 125cc सेगमेंट की बाइक स को काफी जयादा पसंद किया जाता है। रोजाना उपयोग के लिए इस सेगमेंट की बाइक स में जयादा पावर मिलने के साथ ही Milage भी बेहतर मिलती है। किन कंपनियों की ओर से इस सेगमेंट में किन चार बेहतरीन बाइक स को ऑफर फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश में बड़ी संख्या में लोग ऑफिस आने जाने के साथ कई कामों के लिए बाइक का उपयोग करते हैं। ऐसे में दमदार इंजन के साथ ही Milage का भी खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि बाजार में किन चार बाइक्स को 125cc सेगमेंट में इन खूबियों के साथ ऑफर किया जाता है।

TVS Raider 125
टीवीएस की ओर से Raider बाइक को 125 सीसी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इसमें 124.8 सीसी की क्षमता का इंजन दिया जाता है। जिससे 11.4 बीएचपी और 11.22 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस बाइक को एक लीटर पेट्रोल में करीब 67 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसकी कीमत 95 हजार रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट को 1.03 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है।

Hero Xtreme 125 r

देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प की ओर से भी इस सेगमेंट में Xtreme 125 r को ऑफर किया जाता है। बेहतरीन फीचर्स के साथ आने वाली इस बाइक में कंपनी 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन देती है। जिससे बाइक को 11.4 बीएचपी के साथ 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस बाइक को एक लीटर पेट्रोल में करीब 66 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसकी कीमत 95 हजार रुपये से लेकर 99500 रुपये एक्स शोरूम तक है।

Bajaj Pulsar NS125
बजाज की ओर से एनएस सीरीज में पल्सर 125 को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इस बाइक में 124.45 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया जाता है। जिससे बाइक को 12 पीएस और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। Milage के मामले में यह बाइक भी बेहतर है। इसे एक लीटर पेट्रोल में करीब 65 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसकी कीमत एक लाख रुपये एक्स शोरूम है।

Honda SP125
125 सीसी सेगमेंट में होंडा की ओर से भी एसपी125 को ऑफर किया जाता है। इस बाइक की माइलेज करीब 60 किलोमीटर प्रति लीटर है। इसमें कंपनी 123.94 सीसी का इंजन देती है। जिससे इसे 10.72 बीएचपी और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसकी कीमत 86 हजार रुपये एक्स शोरूम से शुरू हो जाती है।

हीरो की दमदार बाइक Maverick 440 की डिलीवरी आज से होगी शुरू, जानें खूबियां और कीमत

देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता Hero Moto corp की ओर से Maverick 440 को भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस दमदार बाइक की डिलीवरी कल से शुरू हो रही है। Hero Maverick 440 में कंपनी की ओर से किस तरह की खूबियों को दिया जाता है। इसकी कीमत व या है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। प्रीमियम बाइक सेगमेंट में Hero की ओर से Maverick 440 को ऑफर किया जाता है। साल की शुरुआत में इस बाइक के लाँन्च के बाद अब इसकी डिलीवरी भी शुरू होने जा रही है। सोमवार से इस बाइक को ग्राहकों को देना शुरू कर दिया जाएगा। हम इस खबर में आपको Hero Maverick 440 की खूबियों के साथ कीमत की जानकारी भी दे रहे हैं।

Hero Maverick 440 की

डिलीवरी कल से शुरू होगी
हीरो मोटोकॉर्प की ओर से Maverick 440 बाइक की डिलीवरी को सोमवार से शुरू कर दिया जाएगा। प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी की ओर से इस फ्लैगशिप बाइक को फरवरी 2024 में लाँन्च किया गया था। लाँन्च के बाद अब अप्रैल में इसकी डिलीवरी को शुरू किया जा रहा है।

किंतना दमदार इंजन
Mavrick 440 बाइक में कंपनी की ओर से 440 सीसी का इंजन दिया जाता है। जिससे बाइक को 27 बीएचपी पावर और 36 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस बाइक के इंजन को लो-एंड टॉर्क को प्राथमिकता देने के लिए कैलिब्रेट किया गया है, जो शहरी इलाकों और एक्सप्रेस वे पर राइडिंग के मामले में काफी बेहतरीन अनुभव देता है।

कैसे हैं फीचर्स
बाइक में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जाता है। इसके फ्रंट में 43 मिमी के टेलीस्कोपिक फोक्स और रियर में

7-स्टेप एडजस्टेबल टिवन शॉक्स ऑनवॉर दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 320 मिमी डिस्क और डुअल-चैनल एबीएस दिया गया है। वहीं, रियर में 240 मिमी डिस्क को दिया गया है। बाइक में 35 से ज्यादा कनेक्टिव फीचर्स को दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें एलईडी लाइट्स, डिजिटल स्पीडोमीटर,

किंतनी है कीमत
कंपनी की ओर से Mavrick 440 को बेस, मिड और टॉप जैसे तीन वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। इस बाइक को एक्स शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपये से शुरू हो जाती है और इसके टॉप वेरिएंट को 2.24 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसके मिड वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 2.14 लाख रुपये है। खास बात यह है कि कंपनी की इस बाइक को जिन ग्राहकों ने 15 मार्च से पहले बुक किया था उनको 10 हजार रुपये की कीमत वाली एक्सेसरीज और Maverick Kit को भी दिया जाएगा।



शिवराज सिंह चौहान का चुनाव लड़ रही हैं बहनें-भांजियां



दीपाली शुक्ला

लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विदिशा से अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के लिए विदिशा सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। यहाँ यदि भाजपा का उम्मीदवार प्रचार करने में भी जाए, तो भारी अंतर से विजय उसके हिस्से आएगी। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। मध्यप्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान उनके नाम है। अपने कार्यकाल में उन्होंने जनता का अभूतपूर्व विश्वास कमाया है, जो सार्वजनिक तौर पर कई बार हमारे सामने आता है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें जिस प्रकार का स्नेह नागरिकों की ओर से मिल रहा है, वैसा कम ही देखने को मिलता है। विशेषकर माताओं-बहनों के साथ उनका आत्मीय संबंध बन गया है। मध्यप्रदेश की महिलाएं सच में उन्हें अपने भाई और लड़कियां उन्हें अपने मामा के तौर पर स्वीकार कर चुकी हैं। वे चुनाव प्रचार के लिए जहाँ भी जा रहे हैं, अनूठे नजारे दिखायी दे रहे हैं। महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पैसे दे रही हैं। छोटी लड़कियां उन्हें अपनी गुल्लक भेंट कर रही हैं। बड़ी बहनें जिस तरह अपने घर आए भाई के हाथ में दस-बीस रुपये थमा देती हैं, वैसे ही नजारे शिवराज सिंह चौहान के चुनाव प्रचार में दिख रहे हैं। ये महिलाएं भी जानती हैं कि उनके दस-बीस रुपये से शिवराज सिंह चौहान का चुनाव खर्च नहीं निकलेगा और वे यह भी जानती हैं कि शिवराज अपना चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम भी हैं। इसके बाद भी महिलाएं अपने शिवराज भैया के हाथ में 10, 20 या 50 रुपये थमा रही हैं, तो उसके पीछे भावनात्मक रिश्ता है। अपनत्व है। साफ दिखायी देता है कि शिवराज सिंह चौहान का चुनाव उनकी 'बहनें और भांजियां' लड़ रही हैं। जब किसी नेता का चुनाव आम जनता लड़ती हुई दिखायी दे तो समझ लीजिए कि उसका राजनीतिक कद क्या होगा। अपनी बहनों-भांजियों से भेंट पाकर शिवराज सिंह चौहान भी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि जनता का यह प्रेम अद्भुत है, इस प्रेम के बदले तोनों लोक का सुख भी कहीं नहीं लगेगा। इस प्रेम को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मेरे बेटा-बेटी भी गुल्लक भेंट कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। स्मरण रहे कि विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के कारण भाजपा को महिलाओं का एक तरफा वोट मिला है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई 'लाड़ली बहना



लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विदिशा से अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के लिए विदिशा सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। यहाँ यदि भाजपा का उम्मीदवार प्रचार करने में भी जाए, तो भारी अंतर से विजय उसके हिस्से आएगी। वहीं, शिवराज सिंह चौहान के लिए तो यह और भी सुरक्षित सीट है। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व वे यहीं से लोकसभा सांसद थे। वर्ष 1990 में नौवीं विधानसभा के लिए शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनकर आए थे। 23 नवंबर, 1991 को ही शिवराज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

योजना' ने पूरा खेल ही बदल दिया था। इसके अलावा भी शिवराज सिंह चौहान की कई योजनाओं ने महिलाओं को भाजपा का मतदाता बना दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए कई नवाचार किए, जिन्हें अन्य राज्यों की सरकारों ने भी अपनाया। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विदिशा से अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के लिए विदिशा सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। यहाँ यदि भाजपा का उम्मीदवार प्रचार करने में भी जाए, तो भारी अंतर से

विजय उसके हिस्से आएगी। वहीं, शिवराज सिंह चौहान के लिए तो यह और भी सुरक्षित सीट है। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व वे यहीं से लोकसभा सांसद थे। वर्ष 1990 में नौवीं विधानसभा के लिए शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनकर आए थे। 23 नवंबर, 1991 को ही शिवराज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विदिशा से तत्कालीन सांसद अटल बिहारी वाजपेयी की सीट रिक्त होने के बाद यहाँ हुए उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद साल 2004 तक लगातार शिवराज सिंह चौहान पांच बार यहाँ से सांसद रहे। लोकसभा

चुनाव में एक तरह से शिवराज सिंह चौहान अपने घर लौटे हैं। भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक भी यह दावा कर रहे हैं कि शिवराज यहाँ से देश की सबसे बड़ी जीत का कीर्तिमान रच सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 2019 में यहीं से भाजपा के रमाकंठ भागवत ने कांग्रेस ने शैलेंद्र पटेल को लगभग पाँच लाख वोटों के भारी-भरकम अंतर से पराजित किया था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनाव प्रचार अभियान का विश्लेषण करने पर ध्यान आता है कि विदिशा संसदीय क्षेत्र के नागरिकों को साथ उनका संबंध बहुत प्रगाढ़ है। इसलिए ही कांग्रेस भी उनके सामने किसी नये और युवा चेहरे को उतारने में संकोच कर गई। कांग्रेस ने अपने उस प्रत्याशी पर दांव लगाया है, जो विदिशा से दो बार यानी 1980 और 84 में सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा का क्षेत्र में दबदबा है। वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी से चुनाव हार गए थे लेकिन संसद के गलियारे में भेंट होने पर अटलजी ने प्रताप भानु की प्रशंसा की थी। प्रताप भानु ने लोकसभा चुनाव में अटलजी को अच्छी चुनौती दी थी। हालांकि आज की परिस्थितियां पहले जैसी नहीं हैं और न ही आज प्रताप भानु शर्मा की क्षेत्र में वैसी पकड़ है। उनका सामने शिवराज सिंह चौहान के रूप में ऐसा राजनेता है, जिसका चुनाव क्षेत्र की जनता स्वयं लड़ रही है।

संपादक की कलम से

भारत का विकास पथ-चुनौतियां और सुधार

वर्तमान में कांग्रेस पार्टी जिस खराब स्थिति में है, उसे देखते हुए, अगर वह किसी तरह चुनाव जीतने में सफल हो जाती है, तो क्या वह अपने घोषणापत्र के वायदों को पूरा कर पाएगी? 'न्याय पत्र' घोषणापत्र, एक 48 पेज का दस्तावेज है जो युवाओं, महिलाओं, किसानों, ... वर्तमान में कांग्रेस पार्टी जिस खराब स्थिति में है, उसे देखते हुए, अगर वह किसी तरह चुनाव जीतने में सफल हो जाती है, तो क्या वह अपने घोषणापत्र के वायदों को पूरा कर पाएगी? 'न्याय पत्र' घोषणापत्र, एक 48 पेज का दस्तावेज है जो युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और समानता से संबंधित 5 स्तंभों पर केंद्रित है और इन क्षेत्रों के तहत 25 वायदे शामिल हैं। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि देश भर के लोगों के इनपुट ने घोषणा पत्र को आकार दिया है और कांग्रेस पार्टी ने इसे अकेले नहीं बनाया है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के प्रभाव का मुकाबला करते हुए भारत के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं सहित विभिन्न समूहों के लिए बेरोजगारी, आर्थिक विकास और न्याय को संबोधित करने और संविधान की रक्षा करने का वायदा किया गया है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने और फर्जी समाचार जैसे मुद्दों से निपटने का वायदा करता है। कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वायदा करते हुए सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने का भी वायदा किया। इसके अतिरिक्त, यह किसानों के लिए एम.एस.पी., स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में सुधार और विदेश नीति में बदलाव का वायदा करता है। इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करना कांग्रेस पार्टी के लिए विशेष रूप से कठिन

होगा, क्योंकि हाल के वर्षों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमरेंद्र सिंह सहित कई प्रमुख राजनेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा, पार्टी काफी समय से स्पष्ट दिशा की कमी से जूझ रही है। अब, आइए उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण पर विचार करें जिन्होंने देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। लेखक और प्रॉक्टर एंड गैबल के पूर्व सी.ई.ओ. गुरचरण दास भारतीय राजनीति की जटिलताओं और आर्थिक सुधारों को लागू करने के महत्व पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर विचार करते हुए, दास ने हाल ही में 'द इकोनॉमिस्ट' पत्रिका के साथ अपनी यात्रा सांझा की। बड़े होते हुए, उन्होंने अति-विनियमित अर्थव्यवस्था और कठोर सरकारी नियमों के साथ देश के संघर्ष को देखा, जैसे पल्टू महामारी के दौरान जब उनकी कंपनी को उच्च मांग को पूरा करने के लिए सजा का सामना करना पड़ा। अनुभव ने उन्हें शास्त्रीय उदारवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया। फिर 1991 में भारत में आर्थिक सुधार हुए, जिससे नई स्वतंत्रता और पहचान की राजनीति और अधिनायकवाद जैसी राजनीतिक चुनौतियां आईं। उनकी तरह कई विचारशील व्यक्ति 2 प्रमुख पृष्ठभूमि-कांग्रेस, जिसमें नए विचारों का अभाव था और भाजपा, जिसमें धार्मिक और सत्तावादी प्रवृत्ति थी, के बीच बंट गए। यह कहानी भारतीय राजनीति की जटिलताओं और विकास और बेरोजगारी को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अर्थव्यवस्था को लागू करने के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करती है। चलिए बेरोजगारी का मुद्दा लेते हैं। विश्व बैंक में दक्षिण एशियाई मुख्य अर्थशास्त्री प्रॉन्जिस्का ओहनसोरोगे के अनुसार, सुधारों के बिना इसे हासिल करना आसान नहीं हो सकता है।

पर्व त्योहार

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

दरअसल लोग निर्णय करने वाले नेता को पसंद करते हैं। कुछ करने का जज्बा ही देशवासी नेता में खोजते हैं। विपक्ष के लाख आरोप प्रत्यारोप, एकजुटता के बावजूद नरेन्द्र मोदी पिछले दो चुनावों में लगातार जनता की पसंद बने रहे और 2024 का चुनाव भी लगभग उसी दिशा में बढ़ता लग रहा है।

अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च की लोकतांत्रिक देशों को लेकर हालिया रिपोर्ट हमारे देश के संदर्भ में इस मायने में चौकाने वाली है कि देशवासियों को डेमोक्रेसी का ऑटोक्रेसी मॉडल अधिक लुभा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार देश की लोकतांत्रिक सरकार को लेकर व्यवस्था को लेकर स्वीडन के बाद दूसरे नंबर पर भारत के लोग संतुष्ट हैं। स्वीडन में जहां 75 फीसदी लोग वहां लोकतांत्रिक सरकार के काम करने के तौर तरीके से संतुष्ट हैं वहीं भारत में 72 प्रतिशत लोग लोकतांत्रिक सरकार के काम करने के तौर तरीकों को पसंद करते हैं। इस साल दुनिया के करीब 50 देशों में चुनाव होने जा रहे हैं। इस मायने में प्यू द्वारा अपने पक्ष में साधने में पूरी तरह सफल रही है। दूसरा यह कि कोई भी पार्टी हो उसके अधिकांश टिकट पैसे वाले लोगों को ही मिलते हैं। जहां तक लोकतंत्र के ऑटोक्रेसी मॉडल की बात है आज नरेन्द्र मोदी पर यह आरोप खुले आम विपक्ष लगाता आ रहा है। पर विगत के पन्ने खोले तो नरेन्द्र मोदी का गुजरात मॉडल ही उन्हें केन्द्र की सत्ता दिलाने में सहायक रहा है। दरअसल देश को हमेशा सख्त मिजाज मजबूत नेता की आवश्यकता महसूस होती रही है। किसी भी दल से सख्त मिजाज

डेमोक्रेसी का ऑटोक्रेसी मॉडल है लोगों की पहली पसंद



नेता सामने आया है तो आमजन ने उसे हाथों हाथ लिया है। नेहरु को उस समय के संदर्भ में लोगों द्वारा महत्व दिया गया तो नेहरु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को ईमानदार और दबंग नेता के रूप में आज भी याद किया जाता है। जय जवान जय किसान जो आज एक कदम आगे बढ़कर जय जवान, जय तरह से अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया था जनसंख्या नियंत्रण सहित कदम उठाये गये उसके प्रशंसक आज भी मिल जायेंगे। प्यू की रिपोर्ट में ऑटोक्रेसी को पसंद करने वाले लोगों की 12 प्रतिशत बढ़ोतरी से साफ समझ में आ जा सकता है कि लोग परिणाम पर नहीं जाते,

आलोचना प्रत्यालोचना को भी खारिज कर देते हैं जब कोई निर्णय लेने में हिचकता नहीं है। नरेन्द्र मोदी के यही बात पक्ष में जाती है कि नरेन्द्र मोदी पर विपक्ष तानाशाही, जुमलेबाज, झूठी बात कहना या ना जाने कितने आरोप लगाते हैं पर 2014 और 2019 के चुनाव परिणाम तो विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। 1370, राम मंदिर, तीन नदियां, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बोलड निर्णय और विदेशी नेताओं के बीच बॉस की भूमिका को देशवासी अपना गौरव समझने लगे हैं। दरअसल यह तरह के अनेक उदाहरण मिल जायेंगे। यही कारण है कि यह चुनाव भी मोदी बनाम विपक्ष के बीच लड़ा जा रहा है। लोकसभा के पिछले दो चुनाव भी मोदी के नाम से ही लड़े गये और जनता ने एक्सोल्स्यूट में जोरिटी देकर सब कुछ साफ कर दिया। हालिया पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव भी बीजेपी

क्षेत्रीय क्षेत्रों के स्थान पर मोदी की गारंटी के नाम से लड़े गये और परिणाम सामने हैं। वर्तमान में डेमोक्रेसी के नए रूप ऑटोक्रेसी में एक ही चेहरा-एक ही नाम पर लड़ा जाता है। 18 वीं लोकसभा के हो रहे चुनावों में भी यही हालात हैं। कहने को भले ही यह कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव की दशा और दिशा नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, असदुद्दीन औवैसी तय करने वाले हैं। नरेन्द्र मोदी बनाम समूचा विपक्ष चुनाव आकार ले चुका है। चुनाव का विगुल बज चुका है। दो चरणों के लिए नामांकन भी पूरा हो चुका है वहीं तीसरे चरण के चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो

चुकी है। पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों के मतदान की तिथि भी नजदीक आ गई है। अब यह तो भविष्य के गर्व में छिपा है कि जनता किस सत्ता की चाबी देती है पर यह साफ है कि जनता डेमोक्रेसी के ऑटोक्रेसी मॉडल को ही पसंद करती है। अब राजनीतिक दलों को यह समझ लेना होगा कि आमजन को मुखर और निर्णय लेने की क्षमता वाला नेता चाहिए और सत्ता में आना है तो आमजन तक यह संदेश जाना जरूरी है। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि लोगों ने ऑटोक्रेसी यानी कि अधिनायकवाद को नहीं अपितु लोकतंत्र के अधिनायकवादी मॉडल को पसंद किया है। देश के 72 प्रतिशत लोगों को लोकतांत्रिक सरकार के कार्य करने के तरीकों को पसंद करना और साथ ही एक ही चेहरा-एक ही नाम को पसंद करना डेमोक्रेसी का ऑटोक्रेसी मॉडल है।

एक शक्तिशाली साधन के रूप में देखा। अम्बेदकर ने सभी को शिक्षा तक पहुंचाने के लिए संघर्ष किया, विशेषकर वंचित समूहों के लिए जिन्हें पहले इस अवसर से बाहर रखा गया था। अम्बेदकर का मानना था कि मानव अधिकारों की अवधारणा के लिए मानवीय गरिमा और आत्म-सम्मान का संरक्षण आवश्यक था। अम्बेदकर का दृष्टिकोण: भारत का सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य काफी हद तक डा. बी.आर. अम्बेदकर द्वारा डिजाइन किया गया था। अम्बेदकर, जिन्होंने सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक समानता को केवल एक इच्छा की बजाय सभी नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा। न्याय और समानता के लिए उनकी अटूट खोज भारतीय समाज में व्याप्त संरचनात्मक अन्याय की गहन समझ पर आधारित थी। अम्बेदकर का दृष्टिकोण सिर्फ एक इच्छा से नहीं आर्थिक था।

भारत में सामाजिक-आर्थिक समानता पर डा. अम्बेदकर का दर्शन

भारतीय संविधान को विकसित करने के लिए जिम्मेदार समिति के प्रमुख के रूप में, डा. बी.आर. अम्बेदकर ने दस्तावेज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अध्ययन का तर्क है कि लोकतंत्र और शासन पर अम्बेदकर के समकालीन विचार भारतीय संविधान में निहित ...

भारतीय संविधान को विकसित करने के लिए जिम्मेदार समिति के प्रमुख के रूप में, डा. बी.आर. अम्बेदकर ने दस्तावेज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अध्ययन का तर्क है कि लोकतंत्र और शासन पर अम्बेदकर के समकालीन विचार भारतीय संविधान में निहित सभी समकालीन मूल्यों में साकार होते हैं। अध्ययन यह भी बताता है कि केवल डा. अम्बेदकर ही अपने सामाजिक रूप से

जागरूक दृष्टिकोण के साथ 'सामाजिक लोकतंत्र' के विचार को पर्याप्त रूप से मूर्त रूप दे सकते थे, जो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय पहलू है। यह सच है क्योंकि वह एक न्यायाधीश के साथ-साथ एक समाज सुधारक भी थे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान, भारतीय संविधान के प्राथमिक वास्तुकार बी.आर. अम्बेदकर ने सही समय पर अपने लोगों की स्वाभाविक नेतृत्व भूमिका संभाली। वह सामाजिक आंदोलनों में शामिल हुए और देश के संविधान की स्थापना में योगदान दिया। भारतीय संविधान के उन अनुच्छेदों पर प्रकाश डाला गया और चर्चा की गई जिन्हें शामिल करने के लिए डा. अम्बेदकर को संविधान सभा से गुजरना पड़ा। आइए यह कहकर निष्कर्ष निकालें कि डा. अम्बेदकर का सबसे बड़ा योगदान ने केवल संविधान था, बल्कि संविधानवाद की उनकी विचारधारा भी

थी। डा. बी.आर. अम्बेदकर कहते हैं कि "जीवन के सभी क्षेत्रों, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक में एक व्यक्ति, एक मूल्य" को प्राप्त करना राज्य संरचना है। 'एक व्यक्ति, एक मूल्य' के आदर्श की प्राप्ति के लिए अन्य पुरुषों द्वारा पुरुषों के धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण को समाप्त करना आवश्यक है। समाजवाद का एक प्रमुख घटक सभी प्रकार के शोषण का अभाव है। भारतीय 'राज्य समाजवाद' में अम्बेदकर का योगदान: एक अर्थशास्त्री के रूप में, उन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि भूमि राज्य की है। उनकी राय में, बुनियादी उद्योगों पर राज्य का एकाधिकार होना चाहिए। डा. अम्बेदकर का मानना था कि समाजवाद में आर्थिक समानता के अलावा राजनीतिक और सामाजिक समानता भी शामिल है। उनका मानना था कि राज्य समाजवाद की संरचना है।

अम्बेदकर ने दावा किया कि जातिगत पूर्वाग्रह सभी आर्थिक प्रणालियों को कमजोर करता है। वंचित और उन्नीचीत वर्गों को मदद के लिए, उन्होंने जीवन बीमा क्षेत्र के राज्य स्वामित्व और प्रबंधन को बढ़ावा दिया, साथ ही जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण को भी बढ़ावा दिया। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत राज्य समाजवाद की नींव बनाते हैं। भारत में जाति व्यवस्था लोकतंत्र के सफल संचालन में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरी है। जाति व्यवस्था संपूर्ण लोकतांत्रिक रीति-रिवाजों के विकास में बाधा बनेगी। एक सच्चे लोकतंत्र के संचालन के लिए जातिगत बाधाएं दूर होनी चाहिए। हालांकि, अम्बेदकर ने महात्मा गांधी को उनकी इस मान्यता के लिए कड़ी फटकार लगाई कि असमानता और अस्पृश्यता कृत्रिम विकृतियां थीं और चतुर्वर्ण (चार जातियां) श्रम का एक आवश्यक विभाजन था।

अम्बेदकर का मानना है कि मार्क्सवादी पद्धति और पारंपरिक नव-शास्त्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का उनका समर्थन एक व्यक्तिगत निर्णय था जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के प्रति उनके समर्पण को भी प्रदर्शित किया। अम्बेदकर ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ मानव अधिकारों के आवश्यक घटक के रूप में आर्थिक अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सोचा कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शोषण और गरीबी के चक्र से बचाने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। सच्ची मुक्ति और समानता प्राप्त करने के लिए अम्बेदकर ने भूमि सुधारों, दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों को आर्थिक अवसरों, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंचाने के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए



एफपीआई इन्वेस्टमेंट लगातार तीसरे माह भी जारी

57,380 करोड़ रुपये हुआ डेट बाजारों में अब तक विदेशी निवेश

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) लगातार तीसरे महीने भी इक्विटी बाजारों में खरीदार बने हुए हैं। अप्रैल के पहले दो सप्ताहों के दौरान एफपीआई इक्विटी बाजारों में 13,347 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। इसके साथ कैलेंडर वर्ष 2024 में इक्विटी बाजारों में एफपीआई का शुद्ध निवेश 24,240 करोड़ रुपये हो गया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि आशाजनक विकास संभावनाओं के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन के कारण एफपीआई धरेलू इक्विटी बाजारों में लगातार निवेश कर रहे हैं।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार का कहना है कि भारत-मारीशस कर संधि में किए गए संशोधनों से छोटी अवधि में एफपीआई निवेश प्रभावित होगा। नई संधि की विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद इसमें सुधार हो सकता है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में भूराजनीतिक स्थिति और ईरान व इजरायल के बीच बढ़ता तनाव भी एफपीआई निवेश के लिए चिंता है। हालांकि, धरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) के पास बड़ी मात्रा में नकदी उपलब्ध है।

खुदरा और उच्च नेटवर्थ (एचएनआई) भी भारतीय बाजारों को लेकर काफी आशाजनक हैं। ऐसे में एफपीआई की ओर से की जाने वाली बिक्री की भरपाई धरेलू निवेश से हो जाएगी।

एफपीआई ने इक्विटी बाजारों में इससे पहले मार्च में 35,098 करोड़ और फरवरी में 1,539 करोड़ रुपये का निवेश किया था। हालांकि, इस वर्ष जनवरी में 25,744 करोड़ रुपये की निकासी की थी। पूरे कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान एफपीआई ने इक्विटी बाजारों में 1,71,107 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था।

इस दौरान चार महीने ऐसे रहे थे, जब एफपीआई ने इक्विटी में 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया था। दिसंबर 2023 के दौरान एफपीआई ने इक्विटी बाजारों में सबसे ज्यादा 66,135 करोड़ रुपये का निवेश किया था। डेट फंडों में लगातार आकर्षित हो रहे विदेशी निवेशक कैलेंडर वर्ष 2024 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लगातार आकर्षित हो रहे हैं और अब तक डेट बाजारों में 57,380 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। यह लगातार चौथा महीना है जब डेट बाजारों में एफपीआई निवेश सकारात्मक बना हुआ है। अप्रैल में अब तक एफपीआई डेट बाजारों में 1,522 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं।

इससे पहले जनवरी में एफपीआई ने डेट बाजारों में 19,837 करोड़ रुपये, फरवरी में 22,419 करोड़ रुपये और मार्च में 13,602 करोड़ रुपये का निवेश किया था। कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान एफपीआई ने भारतीय डेट बाजारों में शुद्ध रूप से 68,663 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इस दौरान दिसंबर 2023 में सबसे ज्यादा 18,302 करोड़ रुपये का शुद्ध



निवेश मिला था।

सात शीर्ष कंपनियों का पूंजीकरण 59,404 करोड़ बढ़ा बीते सप्ताह धरेलू बाजारों में गिरावट के बावजूद बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष-10 में से सात कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 59,404.85 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस दौरान भारतीय एयरटेल के

पूंजीकरण में सबसे ज्यादा 19,029.37 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, ICICI बैंक के पूंजीकरण में 15,363.23 करोड़ रुपये, रिलायंस के पूंजीकरण में 10,250.02 करोड़ रुपये, टीसीएस में 7,507.53 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

बीते सप्ताह आइटीसी के पूंजीकरण में 2,809.06 करोड़, इन्फोसिस के पूंजीकरण में 2,303.73 करोड़ और एसबीआई के पूंजीकरण में 2,141.91 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, एचडीएफसी बैंक के पूंजीकरण में 23,170.58 करोड़, एलआइसी में 13,440.62 करोड़ और एचयूएल में 8,153.08 करोड़ रुपये की गिरावट रही है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव, जानिए आपके शहर में किस भाव बिक रहा तेल

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार 14 अप्रैल को ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले। सरकारी तेल कंपनियों प्रतिदिन छह बजे तेल की कीमतें निर्धारित करती हैं। दिल्ली में रविवार को तेल की कीमत 94.73 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.66 रुपये प्रति लीटर रही। चेन्नई की बात करें तो यहां पेट्रोल 100.73 रुपये और डीजल 95.63 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

नई दिल्ली। तेल की कीमतों में रविवार, 14 अप्रैल को मामूली बदलाव देखने को मिले हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज सुबह 6 बजे अपडेट किए जाते हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं। कुछ राज्यों में इनकी कीमत में मामूली परिवर्तन देखने को मिले हैं। यहां हम आपको देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के आज के रेट को लेकर जानकारी देंगे।

देश के प्रमुख महानगरों में दाम
देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपये प्रति लीटर रही। डीजल की बात करें तो यह 87.66 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।

वहीं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पेट्रोल 104.19 रुपये और डीजल 92.13 रुपये प्रति लीटर है।

कोलकाता की बात करें तो यहां एक लीटर पेट्रोल का रेट 103.93 रुपये और डीजल का रेट 90.74 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल का रेट 100.73 रुपये और डीजल 95.63 रुपये प्रति लीटर है।

प्रमुख शहरों में क्या है दाम
नोएडा - पेट्रोल 94.81 रुपये और डीजल 87.94 रुपये प्रति लीटर

गुरुग्राम - पेट्रोल 95.18 रुपये और डीजल 88.03 रुपये प्रति लीटर

फरीदाबाद - पेट्रोल 95.49 रुपये और डीजल 88.33 रुपये प्रति लीटर

लखनऊ - पेट्रोल 94.63 रुपये और डीजल 87.74 रुपये प्रति लीटर

चंडीगढ़ - पेट्रोल 94.22 रुपये और डीजल 82.38 रुपये प्रति लीटर

शिमला - पेट्रोल 95.28 रुपये और डीजल 87.27 रुपये प्रति लीटर

जयपुर - पेट्रोल 104.86 रुपये और डीजल 90.34 रुपये प्रति लीटर

देहरादून - पेट्रोल 93.45 रुपये और डीजल 88.28 रुपये प्रति लीटर

भोपाल - पेट्रोल 104.45 रुपये और डीजल 91.82 रुपये प्रति लीटर

वैश्विक मैनुफैक्चरिंग हब और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का वादा...

बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में देश के आर्थिक विकास का पूरा रोडमैप पेश किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए मैनुफैक्चरिंग पर खास जोर दिया। उन्होंने भारत को एविएशन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स फार्मा जैसे सेक्टर में साल 2030 तक मैनुफैक्चरिंग हब बनाने की भी बात कही है। बीजेपी का भारत को दुनिया की पांचवीं से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भी वादा है।

नई दिल्ली। पिछले तीन वर्षों के दौरान जब दुनिया की तमाम कई देश आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही थी, तब भारत ने लगातार सात फीसद से ज्यादा की विकास दर हासिल की है। इस उपलब्धि से सभी वैश्विक एजेंसियां भी अर्चभित हैं।

रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से वर्ष 2024 आम चुनाव के लिए जारी भाजपा के घोषणा पत्र में देश की मौजूदा आर्थिक गति का पूरा श्रेय लेते हुए चुनाव में विजयी होने की स्थिति में अपनी आगामी सरकार के आर्थिक एजेंडे का रोडमैप दिया गया है।

भाजपा ने कहा है कि अगले कार्यकाल में इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाया जाएगा। इसमें कम से कम छह ऐसे उद्योगों का जिक्र है जिसमें भारत को एक वैश्विक मैनुफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित करने की बात है जैसे एविएशन, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मासी आदि।

भाजपा का यह घोषणा पत्र उसके भावी आर्थिक एजेंडे को लेकर जो संकेत देता है उससे साफ है कि उनकी सरकार में मैनुफैक्चरिंग पर बहुत ही ज्यादा फोकस रहेगा। इसमें कई ऐसी घोषणाएं हैं जो इस बात को बताती हैं। जैसे पहली बार किसी पार्टी ने भारत को उत्पाद निर्माता देश के तौर पर आगे बढ़ाने व स्थापित करने की बात कही है।

इस क्रम में भारत को वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग का हब बनाने का वादा है। भाजपा ने कहा है कि उसके 10 वर्षों के कार्यकाल में भारत में सीए और डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग प्लांट लगाए गये हैं।

यह घोषणा पत्र एक तरह से भारतीय इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टरों में हो रहे



बदलावों को भी साफ तौर पर दिखाता है। एक दशक तक सत्ता में रहने वाली पार्टी ने सीमेंट, स्टील जैसे पारंपरिक उद्योगों की जगह सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहनों, कृत्रिम हारे और दुर्लभ धातुओं के सेक्टर को लेकर ज्यादा उदासित है।

हाल ही में भारत में पहली बार तीन चिप निर्माता कंपनियों के प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए पीएम मोदी के स्तर पर किये गये थे। अब पार्टी ने कहा है

कि वह भारत को चिप व सेमीकंडक्टर निर्माण का एक वैश्विक हब के तौर पर स्थापित करेगी।

इसी तरह से वैश्विक रेलवे मैनुफैक्चरिंग हब के तौर पर और एविएशन क्षेत्र में मैनुफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करने की बात कही गई है। एविएशन सेक्टर में तो यह बात संभव दिखती है क्योंकि भारत में ही हवाई जहाजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। घोषणा पत्र लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने

कहा कि देश में हाल ही में एक हजार से ज्यादा विमानों का समझौता हुआ है।

इसमें आर्थिक कानूनों को सरल बनाने और ईमानदार करदाता को सम्मान देने की बात है। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी लेकिन यह माना जाता है कि भाजपा में मध्यमवर्ग के आधर दालाओं को राहत देने को लेकर विमर्श चल रहा है। हालांकि इस तरह के संकेत स्वयं पीएम मोदी ने पहले दिये हुए हैं।

साइबर फ्रॉड रोकने के लिए वित्त मंत्रालय सख्त, बैंकों को दिया यह खास फरमान

पिछले कुछ समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ा है। शहरी इलाकों के साथ ही दूरदराज के गांवों में भी लोग धड़ल्ले से डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं। इससे साइबर फ्रॉड का जोखिम भी बढ़ा है। कई बार यह भी देखा गया है कि बैंक या वित्तीय संस्थान सही तरीके से KYC नहीं करते जिससे गड़बड़ी होती है। अब वित्तीय मंत्रालय ने बैंकों को एक सख्त निर्देश दिया है।

नई दिल्ली। पिछले एक दशक में टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास हुआ है। अब बड़ी संख्या में लोग फोन से वित्तीय लेनदेन करने लगे हैं, क्योंकि आसान और सुविधाजनक है। इसमें शहरों के साथ दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के लोग भी शामिल हैं। लेकिन, इस डिजिटलाइजेशन का एक नुकसान यह हुआ है कि इससे बैंकिंग फ्रॉड (Banking Fraud) के मामले भी काफी बढ़ गए हैं।

डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल हर आयु वर्ग के लोग करते हैं। जैसे कि बच्चे, बड़े और बुजुर्ग। इनमें से बहुत से लोगों को तकनीकी जानकारी नहीं होती और वे अनजाने में गोपनीय जानकारी साझा कर देते हैं। कई बार वित्तीय संस्थान भी KYC यानी 'अपने ग्राहक को जानो' प्रक्रिया को गंभीर से पालन नहीं करते। इससे भी फ्रॉड की मुहान्दसा बढ़ जाती है।

इस तरह के मामलों पर अब वित्त मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। उसने BoB ऐप घोटाला (BoB App Scam) और इस तरह के अन्य बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए बैंकों को सख्त



Banking Fraud से बचने के लिए जरूरी है ये बातें

निर्देश दिया है।

क्या है वित्त मंत्रालय का फरमान
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि वित्त मंत्रालय ने बैंकों को ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाएं देने वाले दुकानदारों (मर्चेंट) और बैंकिंग प्रतिनिधि जोड़ने से पहले उनकी गहन जांच यानी KYC करने को कहा है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इस साइबर फ्रॉड पर अंकुश तो लगेगा ही, फाइनेंशियल इकोसिस्टम को भी बेहतर किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के डेटा के मुताबिक, पिछले साल साइबर फ्रॉड के 11,28,265 मामले सामने आए। इनमें साइबर अपराधियों ने लोगों को 7,488.63 करोड़ रुपये का चूना लगाया।

निचले स्तर पर डेटा लीक का खतरा
ग्रामीण इलाकों में दुकानदारों और बैंकिंग

प्रतिनिधियों के पास मजबूत साइबर सिस्टमों की जरूरत नहीं होती। लेकिन, उनके पास बहुत से ग्राहकों की संवेदनशील जानकारी होती है। लेकिन, उनके डेटा में सेंध लगने की गुंजाइश काफी अधिक होती है। यही वजह है कि वित्त मंत्रालय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बैंकिंग प्रतिनिधि जोड़ने से पहले उनकी अच्छे से KYC करने की हिदायत दे रहा है। यह हिदायत उन जगहों के लिए खासतौर पर है, जिन्हें साइबर फ्रॉड का 'गढ़' माना जाता है।

साइबर फ्रॉड से ऐसे निपटें रहें सरकार
केंद्र सरकार ने देशभर में साइबर फ्रॉड के मामलों से सख्ती से निपटने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्रालय ने सभी तरह के साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए इंडियन साइबर फ्रॉड को-ऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) बनावाया है।

रिजर्व बैंक (RBI) भी साइबर फ्रॉड में अंकुश लगाने में प्रयास कर रहा है।

उसका इरादा गैरकानूनी तरीके से कर्ज देने वाले लोन ऐप्स के खिलाफ सख्ती बरतना है। वह इसके लिए एक डिजिटल ईडिया ट्रस्ट एजेंसी (DIGITA) बनाए पर भी विचार कर रहा है, जो लोन ऐप का वेरिफिकेशन करेगी।

क्या क्या है 'BoB वर्ल्ड स्कैम' ?
पिछले साल जुलाई में खबर आई कि बैंक ऑफ बड़ोदा ने अपने ऐप 'BoB वर्ल्ड' पर सख्त अंकुश बरस बढ़ाने के लिए बैंक के ग्राहकों के डेटा के साथ छेड़छाड़ की थी। बैंक ने कथित तौर पर कस्टमर्स की अकाउंट डिटेल को को अन्य कॉन्टैक्ट नंबर के साथ लिंक कर दिया। इसका कसद था, मोबाइल ऐप अधिक रजिस्ट्रेशन दिखाना।

यह मामला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ोदा पर एक्शन भी लिया था। उसने तत्काल बैंक ऑफ बड़ोदा को ऐप पर नए ग्राहक जोड़ने से मना कर दिया था।

डिजिटल भुगतान पर बढ़ा देशवासियों का भरोसा; UPI से अगस्त में हुए 10 अरब से ज्यादा लेनदेन



भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार 30 अगस्त को यूपीआई लेनदेन का आंकड़ा 10.24 अरब हो गया। इन लेनदेन का मूल्य 1518456.4 करोड़ रुपये रहा। जुलाई में यूपीआई लेनदेन की संख्या 9.96 अरब थी जबकि जून में यह 9.33 अरब थी। एनपीसीआई देश में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों का मुख्य संगठन है।

भारत की यूपीआई तकनीक अपनाता चाहते हैं कई देश
अगस्त 2021 में यूपीआई के जरिए लेनदेन का आंकड़ा केवल 3.5 बिलियन था जो दो वर्षों में लगभग तीन गुना बढ़ चुका है।

नई दिल्ली। एकीकृत भुगतान व्यवस्था (UPI) के जरिये लेनदेन का आंकड़ा अगस्त में 10 अरब को पार कर गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, 30 अगस्त को यूपीआई लेनदेन का आंकड़ा 10.24 अरब

होगा। इन लेनदेन का मूल्य 15,18,456.4 करोड़ रुपये रहा। जुलाई में यूपीआई लेनदेन की संख्या 9.96 अरब थी जबकि जून में यह 9.33 अरब थी। एनपीसीआई देश में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों का मुख्य संगठन है।

भारत की यूपीआई तकनीक अपनाता चाहते हैं कई देश
अगस्त 2021 में यूपीआई के जरिए लेनदेन का आंकड़ा केवल 3.5 बिलियन था, जो दो वर्षों में लगभग तीन गुना बढ़ चुका है।

हमारे देश में अब ज्यादातर व्यापारी यूपीआई के जरिए लेनदेन पर भरोसा दिखा रहे हैं। आज के समय करोड़ों की कमाई करने वाले व्यापारी हो या सब्जी बेचने वाले छोटे-मझोले दुकानदार, सभी यूपीआई के जरिए लेनदेन कर रहे हैं।

गौरतलब है कि 35 से ज्यादा देश अब भारत की यूपीआई तकनीक को अपनाना चाहते हैं। जापान उन देशों में शामिल है जिन्होंने हाल ही में यूपीआई को अपनाने में रुचि व्यक्त की है।

डिजिटल भुगतान पर बढ़ा देशवासियों का भरोसा
साल 2016-17 में नोटबंदी के दौरान भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया। साल 2016 में मोदी सरकार ने UPI-BHIM लॉन्च किया था। नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर लोगों ने डिजिटल भुगतान पर भरोसा किया।

इसके बाद कोविड महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान के जरिए देश के ज्यादातर लोग पैसों के भुगतान के लिए बैंक की जगह यूपीआई को चुना और आज के समय हर तरह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यूपीआई पर भारतीयों का अटूट भरोसा है।

पर्यावरण पाठशाला: “पर्यावरण को हमारी जरूरत नहीं, बल्कि हमें पर्यावरण की जरूरत है।” अंकुर

परिवहन विशेष न्यूज

हमें कौन्सी जंगल की इतनी आदत ही सो गई है कि वास्तविकता में इंसान होने के बावजूद हम अपनी इंसानियत पर्यावरण के प्रति भूलते जा रहे हैं। यह जो पेड़ पौधे हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर पा रहे हैं?

सुंदर फूल देखा तो तोड़ लिया, कहीं अच्छे पौधे देखे तो उखाड़ के अपने बाग या गमलों के लिए ले लिया। कोई देखे ना देखे, #Karma देख रहा है। जब नियत साफ होती है, तो उसे इंसान ही नहीं, उसे जगह की बरकत अपने आप होती है।

अक्सर यह देखा गया है कि लोग चोरी-छुपे पर्यावरण को चोट पहुंचाने का पूरा कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह ज्यादा दिन चल नहीं सकता। अभी हाल में कोरोना में हम सबने देख लिया, प्रकृति के विरुद्ध जाकर हमारा जीवन-जीवन न रहकर एक अभिशाप बन जाता है। रद्दोबारा वह गलती ना दोहराएं।

पर्यावरण को हमारी जरूरत नहीं, बल्कि हमें पर्यावरण की जरूरत है। आपको पेड़ लगाना है तो लगाइए, नहीं भी लगाएंगे तो भी पेड़ अपने आप जंगल रूप में उग जाएंगे। आप उन्हें काटिए मत, उन्हें नुकसान मत पहुंचाएं और अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाइए।

आज के समय में, मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति की सुरक्षा। इस दिशा में, सजावटी पौधों का महत्व अग्रणी है, और भविष्य में उनकी महत्वपूर्णता और अहमियत और भी बढ़ जाएगी। आधुनिक जीवनशैली में, लोग अक्सर अपने घरों और आस-पास के क्षेत्रों को सजाने और संवारने के लिए बहुत समय और ध्यान देते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पौधों का उचित रूप से प्रबंधन और उनकी सजावट करना।

परंतु, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम केवल रूप से ही नहीं, बल्कि पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी समझें। कुछ पौधे और वृक्ष ऐसे होते हैं जो हमारे पर्यावरण को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे नीम, पीपल, बरगद, और अन्य। इन पौधों का महत्व न केवल हमारे घर के लिए है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए भी है।

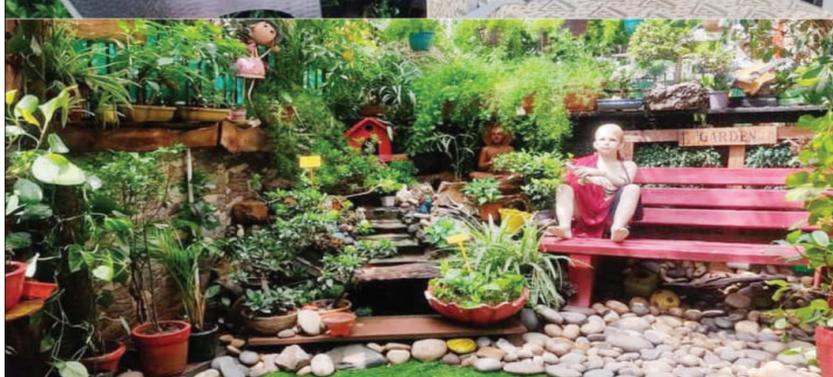
इसलिए, हमें अपने घरों और समुदाय के आस-पास ऐसे पौधों को बढ़ावा देना चाहिए जो पर्यावरण के संतुलन और सजावट को बढ़ावा दें। इससे न केवल हमारे घरों को एक सुंदर और प्रशान्तिपूर्ण दृश्य मिलेगा, बल्कि हमारे पर्यावरण का भी संरक्षण होगा, और हम भविष्य में स्वस्थ और सुखी मिलेंगे।

आज के समाज में, पार्क प्रचुर मात्रा में हैं, फिर भी बहुसंख्यक लोग पौधों को पानी देने के सरल कार्य पर शायद ही ध्यान देते हैं। यह सिर्फ बागवानों का काम नहीं है, प्रकृति के संरक्षण में योगदान देना हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है। किसी पौधे को पानी देना न केवल पौधे के लिए फायदेमंद है, यह आपकी आँखों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुखदायक है, आराम प्रदान करता है। हम गैजेट्स में इतने खो गए हैं कि हम अक्सर प्रकृति से जुड़ना भूल जाते हैं, भले ही हम शारीरिक रूप से पार्कों में मौजूद हों। इस अलगाव के कारण हमारे आस-पास की सुंदरता प्रति सराहना की कमी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पार्कों में कम लोग जाते हैं। गैजेट से दूर रहने और पार्कों के प्राकृतिक वातावरण में डूबने की आदत बनाना आवश्यक है। बिना ध्यान भटकाए पार्कों में समय बिताने से हम वास्तव में प्रकृति की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं और अपने मन को तरोताजा कर सकते हैं।

पार्कों में पौधों को पानी देना प्रकृति से दोबारा जुड़ने और पर्यावरण में सकारात्मक योगदान देने का एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका हो सकता है। इसके अलावा, यह स्मार्टफोन और गैजेट्स पर अत्यधिक स्क्रीन समय के कारण होने वाले तनाव का एक उपाय है, जिससे हमारी आँखों और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को लाभ होता है। आइए अपने व्यस्त जीवन से पीछे हटने, पार्कों की शांत सुंदरता का आनंद लेने और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने का सचेत प्रयास करें। पौधों को पानी देने और वर्तमान क्षण का आनंद लेने जैसे छोटे कदम उठाकर, हम अपने समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण अंतर का अनुभव कर सकते हैं।

पर्यावरण ने आपको बहुत उपहार दिए हैं। आपको सुंदर सुबह, सुंदर शाम, सुंदर वायु, हर कुछ प्रचुर मात्रा में दिया है। हम सभी पर्यावरण के ऋणी हैं, आइए कुछ नैक करें। हम सभी के लिए कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी उपहार ले सकते हैं, लेकिन अपने पर्यावरण के लिए कुछ खर्च करें। हजारों रुपये के वाटर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर तो ले लेते हैं, लेकिन 1000-2000 के अच्छे पौधे लेकर हम अपने माली को नहीं देते। अच्छे पौधे यदि हम देंगे तो वही पौधे आगे चलकर एक सुंदर वृक्ष का निर्माण करेंगे। सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके द्वारा किए गए नैक कार्य में कई सारे पशु-पक्षियों, जीव-जंतुओं को भी आहार, फल, शुद्ध हवा देंगे, तो निश्चय ही एक अच्छे कर्म की तरह, एक अच्छे इंसानियत का फल हम अदा कर पाएंगे।

डिग्रियाँ तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं... इल्म वही है जो किरदार में झलकता है!



संदेशखाली पर एनएचआरसी की रिपोर्ट, टीएमसी ऑफिस में महिलाओं से सामूहिक बलात्कार...

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संदेशखाली मामले पर अपनी रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए हैं। शनिवार को जारी रिपोर्ट में आयोग ने टीएमसी कार्यालय में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार का जिक्र किया है। रिपोर्ट की कॉपी में लिखा गया है कि कम से कम दो महिलाओं ने टीम को बताया कि उनके साथ तुलामूल नेताओं ने रसामूहिक बलात्कार किया, लेकिन पुलिस को घटना की रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। इस रिपोर्ट में एनएचआरसी ने टीएमसी नेताओं शिबू प्रसाद हाजरा, उत्तम सरदार और अमीर अली गाजी को नामित किया है, जिन्होंने कथित तौर पर पार्टी के मजबूत नेता शोख शाहजहां के निर्देशों और संरक्षण के तहत काम किया था। 11 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीणों ने शुरू में टीएमसी डर के कारण अपनी आपबीती बताने से मना कर दिया था पर तालमूल बनाने और उनका विश्वास हासिल करने के बाद उन्होंने टीएमसी के नेताओं के अत्याचार के बारे में बताया। इसमें कहा गया है कि पीटी मीटिंग और स्वयं सहायता समूहों की बैठक के बहाने गांव की महिलाओं को टीएमसी पार्टी कार्यालय में बुला लेते थे और फिर वह महिलाओं को दो रात तक कार्यालय में बिठाते थे और अंधड़ एवं गंदी भाषा का प्रयोग करते थे। युवा और सुन्दर दिखने वाली महिलाओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जाता था। उन्होंने संदेशखाली स्थित टीएमसी कार्यालय के कमरे के अंदर ले जाया गया और



उनका यौन शोषण/सामूहिक बलात्कार किया गया। अन्य महिलाएं से शोषण बनाने, कार्यालय की सफाई और तालाबों की सफाई

जैसे काम करवाए गए। एनएचआरसी ने 21 फरवरी को पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के सुदूर गांव संदेशखाली में

ला यूनिशन 2024 में विद्यार्थियों की आकर्षक प्रस्तुति, पारितोषित वितरण के साथ समापन

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भौलवाड़ा। स्थानीय संगम विश्वविद्यालय भौलवाड़ा में वार्षिक कार्यक्रम सांस्कृतिक, खेलकूद, तकनीकी कार्यक्रम ला यूनिशन 2024 का समापन कार्यक्रम किया गया (समापन कार्यक्रम के रंगारंग कार्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया (समाज को संदेश देती प्रस्तुतियों ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का संकल्प कराया। ला यूनिशन के आयोजन सचिव डा.श्वेता बोहरा ने बताया की दो दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 300 से अधिक छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया तथा दूसरे दिन बॉक्स फुटबॉल, नो फायर नो फस, संगम

रोडीज, कैम्पस पूल पिच, एस्केप रूम, टेबल टेनिस, बिजनेस डंगल, सिंगिंग, डिस्कवाइ एंड ड्रॉ, डायरेक्टर्स कट, सोलो डांस, ग्रुप डांस, ऐआई कल्पना, फैशन शो आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य अतिथि:कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एनसीसी कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजिंदर शर्मा तथा आईएएस निवृत्ति सोमनाथ, भौलवाड़ा उपखंड अधिकारी थे।लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समस्याओं पर आधारित रैप को सराहना करी। आईएएस निवृत्ति सोमनाथ ने इस अवसर पर सभी युवाओं को वोटर अवेयरनेस के बारे में समझाया तथा मतदान की शपथ दिलाई।



छात्रों का, छात्रों के लिए छात्रों के द्वारा कराया ला यूनिशन:विश्वविद्यालय के छात्र संयोजक हर्ष सोमानी ने बताया की संगम विश्वविद्यालय में पहली बार कार्यक्रम छात्रों का, छात्रों के लिए तथा छात्रों के द्वारा कराया गया ला यूनिशन है (जिसकी सफलता के सूत्रधार में कोर स्टुडेंट सदस्य में हर्ष सोमानी, आर्यन

सेठिया, सुधित राज, प्रीतम सिंह, मोहम्मद इजराइल, सेजल संचेती, सूरज, दीपक भट्ट, विश्वजीत, कशिश, निविंता बूलिया, खुशी, अभिनव, जैन, मनीष सिंह, मयंक, फारिमा, मानवेंद्र सिंह, उज्वल, एकलव्य, अमेय पाठक आदि का विशेष सहयोग रहा। विजेताओं को दिया गया मोमेंटो, सर्टिफिकेट:दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर रहे विजेताओं, उपविजेताओं को मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल तेजिंदर शर्मा, आईएएस निवृत्ति, विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. करुणेश सक्सेना, प्रो. प्रिंसिडेंट मानस रंजन पाणिग्रही, रजिस्ट्रार प्रो. राजीव मेहता द्वारा सम्मानित किया गया।

साइबर अपराध में भारत 10वे नम्बर पर...

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। साइबर अपराध के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। दुनियाभर के साइबर अपराध विशेषज्ञों का सर्वेक्षण करने वाले एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक संकलित किया है जो लगभग 100 देशों की रैंकिंग करता है और साइबर अपराध की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार प्रमुख स्थानों की पहचान करता है। इन श्रेणियों में रैसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और घोटाले शामिल हैं। सूची में रूस शीर्ष पर है 'प्लोस वन' जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार इस सूची में रूस शीर्ष पर है और इसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया हैं। उत्तर कोरिया सातवें स्थान पर है, जबकि ब्रिटेन और ब्राजील



क्रमशः आठवें और नौवें स्थान पर थे। शोधकर्ताओं ने जिन प्रमुख श्रेणियों की पहचान की उनमें तकनीकी उत्पाद और सेवाएं जैसे मेलवेयर, रैसमवेयर

सहित बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड सहित डेटा चोरी व अग्रिम शुल्क धोखाधड़ी जैसे घोटाले और धनशोधन करना शामिल हैं। 192 सर्वेक्षण प्रतिक्रियाएं

सर्वेक्षण में टीम को 92 पूर्ण सर्वेक्षण प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। शोधकर्ताओं ने पाया कि शीर्ष छह देश प्रत्येक साइबर अपराध श्रेणी के तहत शीर्ष दस देशों में शामिल थे। लेखकों ने अध्ययन में लिखा है रूस और यूक्रेन में तकनीकी साइबर अपराध की घटनाएं ज्यादा हैं, जबकि नाइजीरियाई साइबर अपराधी साइबर अपराध के कम तकनीकी रूपों में लिप्त हैं। उनमें तकनीकी उत्पाद और सेवाएं जैसे मेलवेयर, रैसमवेयर सहित बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड सहित डेटा चोरी व अग्रिम शुल्क धोखाधड़ी जैसे घोटाले और धनशोधन करना शामिल हैं। घोटालों में भारत आगे अध्ययन के अनुसार भारत घोटालों के मामले में आगे पाया गया इसके अलावा, रोमानिया और अमेरिका में तकनीकी अपराधों के मामले अधिक सामने आये।

भारत-अमेरिका में वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत-अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में हुई प्रगति को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के साझा प्रयासों पर भी चर्चा की गई। भारत के विदेश सचिव विनय कवात्रा और अमेरिकी रक्षा उप मंत्री कैथलीन हिक्स ने इस समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर खासतौर पर बातचीत की। कवात्रा इस सप्ताह अमेरिका में हैं, जहां वह

अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें करेगे और रक्षा एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ बातचीत करेगे। उन्होंने हिक्स के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति को लेकर अपने साझा प्रयासों पर कहा कि यहां सुरक्षा और स्थिरता प्रमुख चुनौती है। और इससे निपटने के लिए संयुक्त कोशिशें जरूरी हैं। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय (पेंटागन) के प्रवक्ता एरिक पैहोन ने बताया, कवात्रा और हिक्स ने भारत-अमेरिकी रक्षा साझेदारी को मजबूत करने

की प्रार्थनिकताओं पर जोर देते हुए द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग के अमल के तरीकों को बढ़ाने का आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों अधिकारियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समर्थन में प्रमुख रक्षा साझेदारी में ऐतिहासिक तेजी को भी रेखांकित किया। लड़ाकू जेट इंजन, बख्तरबंद वाहन उत्पादन की सराहना कवात्रा और हिक्स ने लड़ाकू जेट इंजन और बख्तरबंद वाहनों के सह-उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के प्रयासों की सराहना की। साथ ही अमेरिकी व



भारतीय उद्यमियों व निवेशकों के बीच नवाचार तथा साझेदारी को बढ़ावा देने की कोशिशों को सराहा। सैन्य भागीदारी का दायरा बढ़ाने पर चर्चा

पेंटागन प्रवक्ता एरिक पैहोन ने कहा कि कवात्रा और हिक्स ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा-स्थिरता बढ़ाने के साझा प्रयासों के साथ सैन्य भागीदारी का दायरा बढ़ाने के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र चीन के आक्रामक बर्ताव व खुले-स्वतंत्र हिंद-प्रशांत की प्रतिबद्धता पर भी बात की। रक्षा व ऊर्जा मंत्रालय के अफसरों से भी मुलाकात अपनी अब तक की यात्रा के दौरान कवात्रा ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर सर्वाधिक जोर दिया। कवात्रा ने प्रबंधन एवं संसाधन के लिए उप विदेश

मंत्री रिचर्ड वर्मा, कर्ट कैम्बेल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, रक्षा मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के प्रमुख अफसरों से भी चर्चा की। निवेश बढ़ाने पर जोर भारतीय दूतावास ने कहा, इन चर्चाओं में भारत-अमेरिकी संबंधों, बढ़ते रक्षा और वाणिज्यिक संबंधों, लचीली आपूर्ति शृंखला और समकालीन क्षेत्रीय विकास के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की गई। भारत-अमेरिकी व्यापार परिषद ने कहा, कवात्रा ने निवेश बढ़ाने, नवाचार-प्रौद्योगिकी बढ़ाने पर जोर दिया।